डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 17.02.2025 से 23.02.2025 ▶ वर्ष-42 ▶ अंक-08 ▶ मूल्य ₹ 10.00

ईज-ऑफ-डूइंग से पारदर्शी बनी बिजनेस प्रक्रिया - मुख्यमंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ अब व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार ने व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई दूरदर्शी सुधार लागू किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह पहल राज्य को न केवल देश के भीतर, बल्कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर भी प्रमुख स्थान दिला रही है।

राज्य सरकार ने व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल प्लेटफॉर्म, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सेवाओं को लागू किया है। इन नवाचारों ने प्रदेश को निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया है। ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और स्वीकृति प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण ने प्रक्रियाओं को त्वरित और पारदर्शी बनाया है। इससे उद्यमियों के लिए समय और लागत में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

'स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज़' पहल

इस योजना के तहत उद्योगों को आवश्यक 22 स्वीकृतियां सरल प्रक्रिया के तहत प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, नए व्यवसायों को तीन वर्षों तक विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं, जिससे उद्यमी सशक्त रूप से स्थापित हो सकें।

निवेशकों के लिए सुविधा

'इन्वेस्ट एमपी' पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को सभी आवश्यक अनुमोदनों की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरी करने में सहायता मिलती है। इससे प्रदेश में घरेलू और वैश्विक कंपनियों का विश्वास बढ़ा है। भूमि आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाकर निवेशकों को कम समय में औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में सहायता मिल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली में जीआईएस-2025 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए

मध्यप्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद हैं निवेशकों के लिए निवेश की अपार संभावनाएं- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में इन्वेस्ट एमपी जीआईएस-2025 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में विभिन्न देशों के एम्बेसेडर और डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग की।

- समाज में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण स्थान।
- मध्यप्रदेश की उद्योग एवं निवेश-नीतियां निवेश के लिए फ्रेंडली।
- अनेक देशों ने दिखाई मध्यप्रदेश में निवेश की रुचि
- भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर।
- कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल।
- उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन और राउण्ड टेबल मीटिंग हुई।
- मुख्यमंत्री ने जीआईएस भोपाल के लिए उद्योगपतियों को दिया आमंत्रण।

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में जीआईएस-2025 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में उद्योगपतियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यहां नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों की अपार जल राशि है, निरंतर बिजली उपलब्ध है, वन संपदा है, सड़कों, रेलवे और वायु मार्ग का अच्छा नेटवर्क है और उद्योगों को बड़ी रियायतें हैं। मुख्यमंत्री ने 24 एवं 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंदौर, पहाड़ों और वन संपदायुक्त भोपाल शहर में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें और इन तारीखों को अविस्मरणीय बनाएं।

तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस कार्य में निवेशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत प्राकृतिक संसाधनों के साथ मानव संसाधन में भी आगे है। हम उद्योगों को बढ़ाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी विश्व भर में भारत की प्रगति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है।

अनेक देशों ने दिखाई मध्यप्रदेश में निवेश की रुचि

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के कर्टन-रेजर कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूतों ने मध्यप्रदेश को संभावनाओं से भरपूर निवेश गंतव्य बताते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने शिक्षा, कृषि और कौशल विकास में सहयोग को प्राथमिकता देने की बात कही, जबकि मैक्सिको के राजदूत ने प्रदेश की नीतियों की सराहना करते हुए निवेश संभावनाओं पर सकारात्मक रुख प्रकट किया। अलबानिया के राजदूत ने शहरी नियोजन के क्षेत्र में अपनी रुचि व्यक्त की, वहीं जिम्बाब्वे के राजदूत ने कृषि क्षेत्र में साझेदारी को लेकर उत्साह दिखाया।

/संक्षिप्त खबर/

मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समय निकट है। विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतावासों के माध्यम से प्रदेश में व्यापार और उद्योग की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा, महिला, किसान और गरीबों का जीवन बेहतर हो, इस उद्देश्य से कृषि के साथ उद्योगों को भी प्रदेश में आवश्यक अधोसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग संबंधी इन नीतियों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, नीतियों में राज्य के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार कमजोर से कमजोर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

आचार्य शंकर का सनातन एकता का कार्य पूजनीय है - मुख्यमंत्री

भोपाल, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा अद्वैत वेदान्त दर्शन के लोकव्यापीकरण एवं सार्वभौमिक एकात्मता की संकल्पना के उद्देश्य से महाकुम्भ क्षेत्र के सेक्टर 18 में स्थापित एकात्म धाम मंडपम्, हरीशचंद्र मार्ग में आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर केंद्रित 'शंकरो लोकशंकरः' कथा का शुभारंभ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, श्री योगा नन्देश्वर मठ मैसूर के मठाधिपति श्री शंकर भारती महास्वामी की उपस्थिति में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष, गीता परिवार के संस्थापक स्वामी गोविन्ददेव गिरि महाराज के मुखारविंद से हुआ।

कार्य अद्भुत और अद्वितीय

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने आचार्य शंकर के योगदान और अद्वैत वेदांत पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा "आदि शंकराचार्य का योगदान केवल उनके समय के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। सनातन धर्म के संबंध में उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों की उपयोगिता जितनी स्पष्ट है, उस काल में इसकी कल्पना भी कठिन रही होगी। उनके कार्य अद्भुत और अद्वितीय हैं।

मूलभूत सिद्धांत पुनर्स्थापित हुए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आचार्य शंकर द्वारा सनातन धर्म और सांस्कृतिक एकता के लिए किए गए कार्यों से न केवल धर्म के मूलभूत सिद्धांत पुनर्स्थापित हुए, बल्कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का अद्भुत कार्य भी हुआ। आदि शंकराचार्य के कार्य और विचार आज भी चराचर जगत में पूजनीय हैं और अनंतकाल तक रहेंगे।" मध्यप्रदेश शासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा, "मध्यप्रदेश सरकार इस प्रकल्प के पुनर्जीवन और विस्तार के लिए सदैव साथ है।

जीआईएस देगा मध्यप्रदेश के स्टार्ट-अप्स को नई उड़ान

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न पर काम करते हुए मध्यप्रदेश तेजी के साथ एक मजबूत स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार नवाचार, उद्यमिता और रोज़गार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्ट-अप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपना रही है। हमारा प्रयास मध्यप्रदेश को "स्टार्ट-अप और नवाचार का केंद्र" बनाना है, जहां युवा उद्यमियों को अपने आइडियाज़ को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिले।

प्रदेश में महाशिवरात्रि से आरंभ होगा नवजागरण पर केंद्रित विक्रमोत्सव - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन में विक्रमोत्सव-2025 की आयोजन समिति की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी से विक्रमोत्सव-2025 का आरंभ होगा।

सृष्टिकर्ता महादेव के महोत्सव से सृष्टि के आरंभ दिवस वर्ष प्रतिपदा 30 मार्च तक चलने वाला विक्रमोत्सव, सम्राट विक्रमादित्य के युग, भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या पर केंद्रित रहेगा। इसके अंतर्गत साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही ज्योतिर्विज्ञान, विचार गोष्ठियां, इतिहास और विज्ञान समागम, विक्रम व्यापार मेला, लोक एवं जनजातीय संस्कृति पर आधारित गतिविधियां संचालित होंगी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप के प्रवर्तन, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन, वस्त्रोद्योग, हथकरघा उपकरणों की प्रदर्शनी के साथ क्षेत्रीय, पौराणिक फिल्मों के महोत्सव और श्रीकृष्ण पर केन्द्रित फिल्मों का प्रदर्शन और प्रस्तुतियां भी विक्रमोत्सव का हिस्सा रहेंगे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ ही शोधपरक पुस्तकों, ग्रन्थों का लोकार्पण और विक्रम पंचांग का प्रकाशन भी होगा।

सम्राट विक्रमादित्य के बारे में जानकारी

मुख्यमंत्री ने विक्रम संवत के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि संवत, प्रवर्तन की प्रक्रिया सामर्थ्य और सुशासन पर आधारित है, सम्राट विक्रमादित्य के विविध पक्षों पर जन-जन को जानकारी देने के लिए गतिविधियां संचालित की जाना चाहिए।

अहिल्याबाई पर केंद्रित प्रदर्शनियां लगाई जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमोत्सव में उज्जैन के साथ अन्य स्थानों पर भी सम्राट विक्रमादित्य, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा और देवी अहिल्याबाई पर केंद्रित प्रदर्शनियां लगाई जाएं। भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पक्षों पर प्रसार के लिए गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने भीली, गोंडी जैसी जनजातीय बोलियों के कवियों को भी कवि सम्मेलन में शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित गीत, कविता और रचनाओं को सम्मानित किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि विक्रमोत्सव में होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में ड्रोन और रोबोटिक-शो जैसे आयोजन हों।

8 फरवरी

आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती

● भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट में कटौती की है। रेपो रेट में 25 बेसिस

पॉइंट की कटौती हुई है, जिससे अब मौजूदा रेपो रेट 6.25 प्रतिशत हो गयी है। रेपो रेट में यह कटौती पांच वर्ष बाद की गई है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2020 में रेपो रेट घटाई थी। हालांकि उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी थी। आखिरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी फरवरी 2023 में की गई थी। आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि रेपो रेट में कटौती के बाद अब आपके लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। गवर्नर ने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही है। साथ ही वैश्विक स्तर पर महंगाई भी बढ़ रही है।

● राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने घोषणा की, कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) चार मई को आयोजित की जाएगी। नीट यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और सात मार्च को समाप्त हो जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार से यह देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 24 लाख उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी। एनटीए प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आयोजित करती है। एमबीएसएस कोर्स के लिए कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से करीब 56,000 सीटें सरकारी अस्पतालों में और करीब 52,000 सीटें निजी कॉलेजों में हैं।

9 फरवरी

क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम में रीस्टार्ट परीक्षण हुआ सफल

● भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम

इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। इसरो ने वैक्यूम परिस्थितियों में 'मल्टी-एलिमेंट इग्नाइटर' के साथ एलवीएम-3 के ऊपरी चरण को पावर देने वाले स्वदेशी सीई-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने कहा कि यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। यह इंजन गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजेगा।

● ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण (बीएएस) के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका के कुछ दूरस्थ स्थानों से बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक खोजे हैं। यह पहली बार है जब प्लास्टिक के छोटे कण इतने दुर्गम स्थानों पर मिले हैं। शोधकर्ताओं ने दक्षिणी ध्रुव के दो सुदूर क्षेत्रों, यूनियन और शैन्ज ग्लेशियर के तीन फील्ड कैंपों से एकत्र नमूनों का विश्लेषण किया है। इनमें अधिकतम कण 50 माइक्रोमीटर से भी छोटे थे, जो मानव कोशिकाओं के आकार के बराबर हैं। बीएएस की डॉ. क्लारा मैन्नो के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक बाहरी कपड़ों, शिविर के अंदर और आसपास सुरक्षित मार्गों को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सियों और झंडों के माध्यम से आया होगा।

10 फरवरी

अब मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की दो बार होगी परीक्षा

● मध्यप्रदेश बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मुख्य परीक्षा एक की जगह दो बार आयोजित की जाएगी। दो मुख्य परीक्षाओं का मॉडल गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहले से ही है और अब इसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाएगा। मध्यप्रदेश में बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होने वाली है। दूसरी परीक्षा पहली परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों के लिए रहेगी। यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया है। इसके आधार पर वार्षिक परीक्षा का परिणाम तैयार होगा। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 की परीक्षा से लागू होगा।

● केंद्र सरकार ने पहली बार केंद्रीय भू-जल बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला किया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने बोर्ड के कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव कार्मिक मंत्रालय को भेज दिया है। सरकार ने बोर्ड के कामकाज को मौजूदा जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए उसके ढांचे में परिवर्तन की पहल की है। केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री श्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि पुनर्गठन का उद्देश्य इस संगठन को भूजल प्रबंधन के मामले में तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाना है।

11 फरवरी

अब एक वर्ष में कर सकेंगे बीएड और एमएड

● राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) एक वर्षीय बीएड और एक वर्षीय एमएड कोर्स शुरू करेगी। इसके लिए मसौदा विनिमय जारी कर दिया गया है। ये कोर्स शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होंगे। हालांकि एक वर्षीय एमएड कोर्स शुरू होने के बाद मौजूदा दो वर्षीय एमएड कोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। एनसीटीई के अध्यक्ष श्री पंकज अरोड़ा ने कहा कि एक वर्षीय एमएड कार्यक्रम पूर्णकालिक होगा, जबकि दो वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए पेश किया जाएगा जो शिक्षक और शिक्षा प्रशासक जैसे कामकाजी हैं। मसौदा नियमों के अनुसार एक वर्षीय बीएड कोर्स के लिए केवल वे ही पात्र होंगे, जिन्होंने चार वर्षीय प्रेजुएशन डिग्री या पीजी डिग्री पूरी की है। तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए दो वर्षीय बीएड प्रोग्राम जारी रहेगा।

● कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के दिशा-निर्देशों में बदलाव करते हुए फसलों की खरीद सीमा बढ़ा दी है। अब किसानों से 20 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत तक फसलें खरीदी जाएंगी। यह फैसला टमाटर, प्याज और आलू जैसी शीघ्र खराब होने वाली फसलों की बाजार की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को यह विकल्प मिलेगा कि वे किसानों के बैंक खातों में सीधे बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर जमा करें, जिससे किसानों को तत्काल राहत मिल सके। एमआईएस योजना तभी लागू होगी, जब बाजार मूल्य पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में दस प्रतिशत गिर जाए।

12 फरवरी

एनटीए ने जेईई के जनवरी सत्र का परिणाम जारी किया

● नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन-2025 के जनवरी सत्र के नतीजे घोषित किए हैं। 14 उम्मीदवारों ने पूरे 100 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं। इनमें 13 पुरुष और एक महिला है। राजस्थान के आयुष सिंघल ने समग्र प्रथम रैंक हासिल की, उसके बाद कर्नाटक के कुशाग्र गुप्ता और दिल्ली-एनसीटी के दक्ष का स्थान रहा। आंध्रप्रदेश की साई मनोगना गुथिकोंडा 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल करने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं। शीर्ष 2.5 लाख रैंक धारक जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर आईआईटी में प्रवेश के लिए 18 मई को जेईई एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करेगा।

● भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहायता के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' विकसित किया। इसका उपयोग बाहरी अंतरिक्ष में कमांड और नियंत्रण प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा। शक्ति एक खास तरह का सिस्टम कस्टम प्रोसेसर है जिसका डिजाइन रिस्क-5, एक ओपन-सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (आईएसए) पर आधारित है। 'शक्ति' को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से 'डिजिटल इंडिया रिस्क-5' पहल (डीआईआर-5) के तहत तैयार कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर आधारित उन उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना है जो रिस्क-5 तकनीक को अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास सुरक्षा और दृश्यता प्रदान करते हैं।

13 फरवरी

यूपीएससी ने आवेदन प्रक्रिया में किया बदलाव

● संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। यह बदलाव दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन के समय तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद किया गया है। आयोग ने ऐसी शिकायत के बाद पिछले दिनों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया था। यूपीएससी की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ प्रविष्टियों को संपादित करने योग्य बनाया गया है। यह एक बार ही किया जा सकता है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा के आधार पर नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी वाले वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल कॉलम में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

● विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपने 'केंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स' (यूजीसी-केयर) सूची को बंद करने की घोषणा की और उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रकाशनों और पत्रिकाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं के तंत्र विकसित करने की सिफारिश की। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप लिया गया है। इसके अलावा, यूजीसी ने संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा सहकर्मी-समीक्षित (पीयर-रिव्यूड) पत्रिकाओं के चयन के लिए सुझाए गए मापदंड तैयार किए हैं। इन मापदंडों को विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया है। यह 25 फरवरी, 2025 तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं। यूजीसी-केयर की सूची को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सिर्फ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को मान्यता देना था ताकि संकाय चयन, पदोन्नति और शोध निधि में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और शोध गुणवत्ता तथा शोषणकारी (प्रिडेटरी) पत्रिकाओं से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।

14 फरवरी

लोकसभा में नया इनकम टैक्स विधेयक हुआ पेश

● वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक को आगे विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। यह विधेयक इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम, 2025 के रूप में जाना जाएगा। नए विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति की तरह माना जाएगा। इन पर प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और शेयर की तरह

टैक्स लगेगा। हालांकि डिजिटल एसेट्स पर फ्लैट 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। प्रस्तावित नए कानून में, आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित 'पिछले वर्ष' शब्द को बदलकर 'कर वर्ष' कर दिया गया है। इसके साथ ही, मूल्यांकन वर्ष की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। विधेयक में अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्ताव है। आयकर विभाग अब टैक्स से जुड़ी योजनाएं बिना संसद से संपर्क करे शुरू कर सकेगा। विधेयक में आयकर की भाषा को सरल बनाने के साथ गैर-जरूरी करीब 300 से अधिक प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को हटाने का भी प्रस्ताव है।

● अमेरिका में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क ने संघीय सरकार से सभी एजेंसियों को खत्म करने की पैरवी की है। मस्क ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिकी सरकार में क्रांतिकारी बदलाव लाने के अभियान के तहत तमाम संघीय एजेंसियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मस्क ने दुबई में विभिन्न देशों की सरकारों के शिखर सम्मेलन को वीडियो काल के माध्यम से संबोधित किया। मस्क ने कहा कि हमें संपूर्ण एजेंसियों को खत्म करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने सरकारी खर्चों में कटौती और सरकार की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने के अभियान के तहत सरकारी दक्षता विभाग का गठन किया है और मस्क को इसका प्रमुख बनाया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

AIMR EXCEL BEYOND
APEX INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH, INDORE
(Approved by AICTE, MP Higher Education & Affiliated to DAVV, Indore)
REQUIRED FACULTY MEMBERS FOR
MBA, B.Com (Plain, C.A. & Tax procedure) and B.A
■ Principal/ Director ■ Associate Professor's
■ Professor's ■ Assistant Professor's
Qualifications and Pay Scale as per UGC Norms.
Interested candidates may apply /mail with complete resume & testimonials along with two passport size photographs within 15 days for Under Code 28 Selection of DAVV University, Indore
UG-12-13, Royal Platinum, Sch.No.54, Vijay Nagar, Indore(M.P) 452010
Contact Number: 07389919192, 08878880866, Email: hr@aimrindore.com
Contact
R-50590/2025

ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & SCIENCE
A.B.Road Dhamnod, Dhar (M.P.) – 454552
(Affiliated to D.A.V.V. Indore) NAAC Accredited "B" Grade College
E-Mail : adarshinst@gmail.com,Contact : 98935-37647,9644493342
Require
Professor, Associate Professor, Asst. Professor –(Under College Code – 28)
◆ Mathematics – 02 ◆ Commerce – 02 ◆ Computer Science -02
◆ Chemistry – 02 ◆ Botany – 02 ◆ Political Science - 02
◆ Physics – 02 ◆ Hindi – 02 ◆ Sociology- 02
◆ Zoology – 02 ◆ English– 02 ◆ Librarian– 01
◆ Biotechnology–02 ◆ Sports Officer- 01 ◆ LabTechnician- 02
◆ Life Science - 02 ◆ Management - 02
▸ Qualification & Experience as per U.G.C. norms, Salary ad per Norms.
▸ Apply within 10 Days with Full Details and Attested Copies & testimonial send to college E-mail.
R-50585/2025

वर्ष 42, अंक 08 17.02.2025 से 23.02.2025
रोज़गार और निर्माण
www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - डॉ. सुधाम खाड़े
● सम्पादक - रंजना चितले
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
● आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

आर्थिक विकास की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री ने की लोकल से ग्लोबल तक की यात्राएं

मध्यप्रदेश ने बीते एक वर्ष में औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में न केवल रणनीतिक नीतियां बनाई गई हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। बीते एक वर्ष में मध्यप्रदेश ने 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं को मजबूती दी। इसके साथ ही 5 प्रमुख रोड शो आयोजित कर निवेशकों के साथ सीधा संवाद किया गया, जिससे प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को व्यापक मंच मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने 3 देशों-यूके, जर्मनी और जापान की यात्रा कर वहां की प्रमुख कंपनियों और निवेशकों से संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक विकास को मजबूती देने के लिए लोकल से ग्लोबल तक सतत यात्रा जारी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश का नया माहौल बना और वैश्विक उद्योग जगत ने मध्यप्रदेश को अपनी विस्तार योजनाओं में प्राथमिकता देना शुरू किया। अब यह यात्रा और आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने वर्ष-2025 को 'उद्योग वर्ष' घोषित किया है जिससे औद्योगिक विकास के लिए वर्ष भर गतिविधियां होंगी। भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक और बड़ा कदम है, जहां दुनिया भर के निवेशक, उद्योगपति और नीति निर्माता मध्यप्रदेश की अपार संभावनाओं का हिस्सा बनेंगे। यह यात्राएं प्रदेश के औद्योगिक सशक्तिकरण को दर्शाती हैं साथ ही इसे देश के अग्रणी औद्योगिक केंद्रों में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को भी सिद्ध करती हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने आर्थिक प्रगति की एक सशक्त और दूरदर्शी कार्ययोजना के साथ निवेश आकर्षित करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। यह केवल औद्योगिक विस्तार का प्रयास नहीं, बल्कि प्रदेश को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने की रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनाई गई स्पष्ट, दूरगामी और व्यवहारिक नीति ने निवेशकों के विश्वास को मजबूत किया है। सूक्ष्म योजना, सतत संवाद और ठोस नीतिगत सुधारों के जरिये निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप आधारभूत संरचना को विकसित किया गया है। इससे मध्यप्रदेश एक आदर्श औद्योगिक स्थान के रूप में उभर रहा है। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं का सूक्ष्म अध्ययन कर स्थानीय से वैश्विक स्तर तक निवेश आकर्षित करने की रणनीति अपनाई गई, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मंचों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। संभागीय स्तर पर निवेश अवसरों को सशक्त करने के लिए पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। इनमें स्थानीय उद्यमियों, नीति-निर्माताओं और संभावित निवेशकों को एक मंच पर लाकर क्षेत्रीय औद्योगिक क्षमताओं को उजागर किया गया। प्रत्येक संभाग की आर्थिक विशेषताओं के आधार पर उद्योगों को लक्षित किया गया। इससे उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल और सागर में निवेशकों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। इन आयोजनों से स्पष्ट हुआ कि औद्योगिक विकास को जिला स्तर तक ले जाना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह प्रदेश की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संभागीय स्तर पर निवेशकों की रुचि और आवश्यकताओं को समझने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया गया। बेंगलुरु, कोयंबटूर, मुंबई और कोलकाता जैसे औद्योगिक नगरों में रोड-शो आयोजित कर संभावित निवेशकों से सीधा संवाद किया गया। आईटी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, माइनिंग, नवकरणीय ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों से चर्चा कर उनके सुझावों के आधार पर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों को और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया गया। जीआईएस का यह आयोजन न केवल प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा, बल्कि इसे भारत के औद्योगिक भविष्य का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम भी साबित होगा।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर से विकास और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी गति

भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस यात्रा से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर सहमति बनने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट व्यापार से लेकर विकास से जुड़े कार्यों के लिये बहुत आवश्यक है। यह कॉरिडोर एशिया, फ्रांस की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने की रणनीतिक पहल है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कॉरिडोर रेलवे, शिपिंग मार्गों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित करेगा। इससे मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप तक बिना किसी रुकावट के व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। यही नहीं इस कॉरिडोर के निर्माण से बेहतर परिवहन और संचार लिंक को बढ़ावा भी मिलेगा और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में दो अलग-अलग कॉरिडोर शामिल हैं। ईस्ट कॉरिडोर, जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और नॉर्थ कॉरिडोर जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है। कॉरिडोर में रेल, जहाज से रेल संपर्क और सड़क नेटवर्क सहित परिवहन स्ट्रक्चर शामिल हैं। इस कॉरिडोर के निर्माण से भारत को यूरोप तक तेज़ और अधिक कुशल शिप मूवमेंट की सुविधा मिलने की उम्मीद है। जिसमें स्वेज़ नहर समुद्री मार्ग की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत तेज़ पारगमन समय और लागत में 30 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। वहीं इस कॉरिडोर निर्माण और इसके क्रियान्वयन में फ्रांस का मार्सिले बंदरगाह प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। यहां से प्रत्येक वर्ष करीब 100 मिलियन टन माल गुजरता है। यह कॉरिडोर भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक गतिविधियों में आने वाली लागत को कम करने में मददगार साबित होगा।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

11 फरवरी - पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि विशेष

पंडित दीनदयाल जी का आर्थिक चिंतन और समर्थ समाज का निर्माण

'मानव जीवन के उद्देश्य का विचार करके हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे गति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें'

● डॉ. मोहन यादव

व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का दर्शन देने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, एकात्म मानव दर्शन तथा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कोटिशः नमन।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ऋषि-राजनेता रहे जिन्होंने राजनैतिक चिंतन के लिए एकात्म मानवदर्शन का सूत्र दिया और शासन की नीतियां बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दीनदयाल जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र जीवन दर्शन के दृष्टा हैं। पंडित जी द्वारा लगाए गए जनसंघ के पौधे का विस्तार विचार के रूप में देश ही नहीं दुनिया में भी हुआ है। उन्होंने एक ऐसी राजनैतिक धारा निर्मित की जिसका लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है। उनका मानना था कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं अपितु समाज की सेवा के लिए हो, स्वतंत्रता के साथ भारत राष्ट्र की यात्रा भारतीय दर्शन के अनुरूप होनी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल जी के आर्थिक चिंतन को धरातल पर उतारा है। उनके मार्गदर्शन में हम विरासत से विकास की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो अंत्योदय लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दीनदयाल जी का कहना था कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं हो जाता तब तक विकास सही अर्थों में संभव नहीं है। इसी भाव को धरातल पर उतारते हुए मध्यप्रदेश में सात रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इससे प्रदेश के हर अंचल, हर क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता, क्षमता, मेधा और दक्षता को अवसर मिलेगा। प्रदेश का हर व्यक्ति इससे जुड़ेगा और विकास की धारा में शामिल होगा। यह समिट एक तरफ जहां प्रदेश के कोने-कोने से और गांव-गांव से लोगों को उद्योग से जोड़ेगी वहीं विश्व पटल पर उनके उत्पादों को पहचान दिलायेगी।

पंडित जी ने भारत के भविष्य की कल्पना वेदों में वर्णित चार पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर की थी। यह चारों पुरुषार्थ मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर के संतुलन से संभव हैं। इससे ही एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। पहला पुरुषार्थ धर्म है जिसमें शिक्षा, संस्कार और व्यवस्था है तो दूसरे अर्थ में साधन, संपन्नता और वैभव आता है। अर्थ उपार्जन सही तरीके से हो, इसके लिये पंडित दीनदयाल जी ने मानव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस तरह धर्मानुकूल, अर्थात उचित मार्ग से अर्थ उपार्जन करने का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा पुरुषार्थ है काम, जिसमें मन की समस्त कामनाएं शामिल हैं। मनुष्य को संतुलित, समयानुकूल और सकारात्मक स्वरूप में कार्य करना चाहिए। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, अर्थात संतोष की परम स्थिति। यदि व्यक्ति संतोषी होगा तो वह समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार बन सकता है। इन चार पुरुषार्थों की अवधारणा के अनुसार, यदि व्यक्ति और समाज को विकास के अवसर दिये जायें तो स्वावलंबी और समर्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।

पंडित दीनदयाल जी ने राष्ट्र निर्माण और भविष्य की संकल्पना को लेकर गहन चिंतन किया, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप राष्ट्र की चित्ति से विराट तक की कल्पना थी। उनके विकास का आधार एकात्म मानव दर्शन है। इसमें संपूर्ण जीवन की रचनात्मक दृष्टि समाहित है। उन्होंने विकास की दिशा को भारतीय संस्कृति के एकात्म मानवदर्शन के मूल में खोजा। हमारी संस्कृति संपूर्ण जीवन, संपूर्ण सृष्टि का समग्र विचार करती है। यही एकात्म भाव व्यष्टि से समष्टि की रचना करता है। यही पंडित दीनदयाल जी के विकास का व्यापक पक्ष है, सार्वभौम है, प्रासंगिक है। इसमें श्रीकृष्ण के वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा से लेकर आज के ग्लोबलाइज्ड युग का समावेश है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पंडित दीनदयाल जी की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। दीनदयाल जी का मानना था कि अर्थव्यवस्था जितनी विकेन्द्रीकृत होगी उतनी नीचे तक जाएगी और यही स्वदेशी भाव के साथ सृजन का आधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक विकास को लेकर जो कदम उठाये जा रहे हैं उसके मूल में दीनदयाल जी का अर्थदर्शन ही है। पंडित दीनदयाल जी ने भारत की कृषि, उद्योग, शिक्षा और आर्थिक नीति कैसी हो इन सबका विस्तार में उल्लेख किया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल जी के आर्थिक चिंतन को धरातल पर उतारा है। उनके मार्गदर्शन में हम विरासत से विकास की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो अंत्योदय लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दीनदयाल जी का कहना था कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं हो जाता तब तक विकास सही अर्थों में संभव नहीं है। इसी भाव को धरातल पर उतारते हुए मध्यप्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इससे प्रदेश के हर अंचल, हर क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता, क्षमता, मेधा और दक्षता को अवसर मिलेगा। प्रदेश का हर व्यक्ति इससे जुड़ेगा और विकास की धारा में शामिल होगा। यह समिट प्रदेश के कोने-कोने से और गांव-गांव से लोगों को उद्योग से जोड़ेगी और विश्व पटल पर उनके उत्पादों को पहचान दिलायेगी।

इसके लिये हमने यूके, जर्मनी और जापान की यात्रा की है। हैदराबाद, कोयंबटूर तथा मुंबई में रोड-शो कर उद्योगपतियों को निवेश के लिये आमंत्रित किया है। क्षेत्रीय से लेकर ग्लोबल स्तर तक उद्योग के लिये किया गया यह पहला नवाचार है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम 24-25 फरवरी, 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं। यह समिट दीनदयाल जी के स्वदेशी और विकेन्द्रीकरण के चिंतन को सार्थक करेगी। हमारे उद्योग और व्यवसाय की श्रृंखला में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ पायेगा और अंत्योदय का लक्ष्य पूर्ण होगा।

दीनदयाल जी ने विकास को लेकर कल्पना की थी कि विश्व का ज्ञान और आज तक की अपनी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम गौरवशाली भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक देश को विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिये लोकल से ग्लोबल को जोड़ने का जो प्रयास किया है उसके परिणाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दिखाई देंगे। मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास पंडित दीनदयाल जी के आर्थिक विकास के चिंतन अनुरूप विकसित मध्यप्रदेश निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

लेखक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं

भारतीय नौसेना

विभिन्न प्रविष्टियों-जनवरी 2026 (एसटी 26) पाठ्यक्रम के लिए लघु सेवा आयोग अधिकारियों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है

08 फरवरी, 2025 से ऑनलाइन आवेदन करें **ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि- 25 फरवरी, 2025**

1. भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) एझिमाला, केरल में जनवरी 2026 से शुरू होने वाले पाठ्यक्रम के लिए लघु सेवा आयोग (एसएससी) के अनुक्रम हेतु पात्र अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा रखे गए अनुसार राष्ट्रीयता की शर्तों को पूरा करना होगा.

पात्रता शर्तें

2. शैक्षिक योग्यताएं

	क्र. सं.	शाखा/काडर	इंजीनियरी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक के पात्र स्ट्रीम और अन्य योग्यताएं	रिक्ति	लिंग	तिथियों के बीच पैदा होना (दोनो तिथियां मिलाकर)
कार्यकारी शाखा	क.	कार्यकारी शाखा [जीएस (एक्स)/हाइड्रो काडर]	न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी अनुशासन में बीई/बी.टेक.	60 (08 हाइड्रो सहित)	पुरुष और महिलाएं [जीएस (एक्स) में अधिकतम 10 रिक्तियां और हाइड्रो में महिलाओं के लिए 02 रिक्ति]	02 जनवरी 2001 से 01 जुलाई 2006*
	ख.	पायलट	न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी अनुशासन में बीई/बी.टेक. (उम्मीदवार के पास कक्षा 10वीं में कुल 60% अंक हों और कक्षा 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी में न्यूनतम 60% अंक हों).	26	पुरुष और महिलाएं (महिलाओं के लिए अधिकतम 05 रिक्तियां)	02 जनवरी 2002 से 01 जनवरी 2007**
	ग.	नौसेना वायु ऑपरेशन्स अधिकारी (निरीक्षक)		22	पुरुष और महिलाएं (महिलाओं के लिए अधिकतम 05 रिक्तियां)	02 जनवरी 2002 से 01 जनवरी 2007
	घ.	एयर ट्रैफिक नियंत्रक (एटीसी)		18	पुरुष और महिलाएं	02 जनवरी 2001 से 01 जनवरी 2005
	ङ.	लॉजिस्टिक्स	(i) प्रथम श्रेणी के साथ किसी भी अनुशासन में बीई/बी.टेक या (ii) प्रथम श्रेणी के साथ एमबीए, या (iii) प्रथम श्रेणी के साथ बी.एससी/बी.कॉम/बी.एससी (आईटी) के साथ वित्त/लॉजिस्टिक्स/आपूर्ति शृंखला प्रबंधन/सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या (iv) प्रथम श्रेणी के साथ एमसीए/एम.एससी (आईटी)	28	पुरुष और महिलाएं (महिलाओं के लिए अधिकतम 06 रिक्तियां)	02 जनवरी 2001 से 01 जुलाई 2006
शिक्षा शाखा	च.	शिक्षा	(i) एम.एससी (गणित/ऑपरेशनल अनुसंधान) में 60% अंकों के साथ बी.एससी में भौतिकी.	7	पुरुष और महिलाएं	02 जनवरी 2001 से 01 जनवरी 2005
			(ii) एम.एससी (भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी) में 60% अंकों के साथ बी.एससी में गणित.			
			(iii) एम.एससी रसायन विज्ञान में 60% अंकों के साथ बी.एससी में भौतिकी.			
			(iv) मैकेनिकल इंजीनियरी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई/बी.टेक.	8	पुरुष और महिलाएं	02 जनवरी 2001 से 01 जनवरी 2005
			(v) न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई/बी.टेक (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरी)			
			(vi) निम्नलिखित शाखाओं में से किसी एक में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.टेक में 60% अंक:- (a) थर्मल/उत्पादन इंजीनियरी/मशीन डिजाइन में एम.टेक (b) कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार इंजीनियरी/वीएलएसआई/ पावर सिस्टम इंजीनियरी में एम.टेक.		पुरुष और महिलाएं	02 जनवरी 1999 से 01 जनवरी 2005
			नोट: शिक्षा प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60% अंक और कक्षा 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए होने चाहिए.			
तकनीकी शाखा	छ.	इंजीनियरी शाखा [सामान्य सेवा (जीएस)]	न्यूनतम 60% अंकों के साथ निम्नलिखित स्ट्रीम में बीई/बी.टेक: (i) मैकेनिकल/मैकेनिकल विद ऑटोमेशन; (ii) मरीन इंजीनियरी; (iii) इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी; (iv) उत्पादन इंजीनियरी; (v) एयरोनॉटिकल इंजीनियरी; (vi) औद्योगिक इंजीनियरी व प्रबंधन; (vii) नियंत्रण इंजीनियरी; (viii) एयरो स्पेस इंजीनियरी; (ix) ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरी; (x) मेटालर्जी इंजीनियरी; (xi) मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरी; (xii) इंस्ट्रूमेंटेशन व नियंत्रण	38	पुरुष और महिलाएं (महिलाओं के लिए अधिकतम 08 रिक्तियां)	02 जनवरी 2001 से 01 जुलाई 2006*
	झ.	इलेक्ट्रिकल शाखा [सामान्य सेवा (जीएस)]	न्यूनतम 60% अंकों के साथ निम्नलिखित स्ट्रीम में बीई/बी.टेक:- (i) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी; (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी; (iii) इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स; (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन; (v) इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन; (vi) टेलीकम्यूनिकेशन; (vii) अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन (एईसी); (viii) इंस्ट्रूमेंटेशन; (ix) इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंटेशन; (x) इंस्ट्रूमेंटेशन व नियंत्रण; (xi) अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंटेशन; (xii) पावर इंजीनियरी; (xiii) पावर इलेक्ट्रॉनिक्स	45	पुरुष और महिलाएं (महिलाओं के लिए अधिकतम 09 रिक्तियां)	02 जनवरी 2001 से 01 जुलाई 2006
	ञ.	नौसेना कंस्ट्रक्टर	न्यूनतम 60% अंकों के साथ निम्नलिखित स्ट्रीम में बीई/बी.टेक:- (i) मैकेनिकल/मैकेनिकल के साथ ऑटोमेशन; (ii) सिविल इंजीनियरी; (iii) एयरोनॉटिकल इंजीनियरी; (iv) एयरो स्पेस इंजीनियरी; (v) मेटालर्जी; (vi) नौसेना आर्किटैक्चर; (vii) ओशियन इंजीनियरी; (viii) मरीन इंजीनियरी; (ix) शिप प्रौद्योगिकी; (x) शिप बिल्डिंग; (xi) शिप डिजाइन	18	पुरुष और महिलाएं	02 जनवरी 2001 से 01 जुलाई 2006

नोट (1)

क. पैरा 2 में उल्लिखित रिक्तियां अनंतिम हैं और प्रशिक्षण स्लॉट की उपलब्धता पर बदल सकती हैं.

ख. सबमरीन आर्म

(i) जीएस (एक्स), जीएस (इंजीनियरी) और जीएस (इलेक्ट्रिकल) के लिए लघुसूचीबद्ध पुरुष उम्मीदवार, चिकित्सा स्वस्थता, रिक्तियां और सेवा अपेक्षाओं पर सबमरीन आर्म के लिए इच्छुक उम्मीदवार भी पात्र होंगे. इन शाखाओं के विकल्प का चयन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सबमरीन विशेषज्ञता के लिए विकल्प अतिरिक्त अंकित करना होगा.

(ii) बाद के चयन/नामांकन को सबमरीन चिकित्सा (आईएनए से जुड़ने के बाद) को पास करने और सेवा अपेक्षाओं पर सबमरीन विशेषज्ञता से गुजरना होगा.

(iii) मौजूदा नियम के अनुसार सबमरीन प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को सबमरीन भत्ता स्वीकार्य होगा.

ग. **रिमोटली पायलटड एयरक्राफ्ट (आरपीए) विशेषज्ञता** जीएस (एक्स) के अधीन चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा स्वास्थता और सेवा अपेक्षाओं पर आरपीए (आईएनए का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद) में विशेषज्ञता से गुजरने के लिए नामांकित किया जाएगा.

घ. ***मर्चेंट नेवी कार्मिक.**

(I) दूसरे मेट, मेट या मास्टर के रूप में भारत सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का सक्षमता का प्रमाणपत्र (फॉरेन गोइंग) रखने वाले उम्मीदवार और **02 जनवरी 1996 से 01 जुलाई 2006 (दोनों तिथियां मिलाकर)** के बीच पैदा हुए उम्मीदवार पैरा 2(क) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यकारी शाखा प्रवेश (सामान्य सेवा) के लिए आवेदन कर सकता है.

(II) सरकार द्वारा स्टीयरिंग के प्रंथम श्रेणी अभियंता के रूप में भारत सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय के सक्षमता का प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार और **02 जनवरी 1996 से 01 जुलाई 2006 (दोनों तिथियां मिलाकर)** पैरा 2(ख) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार तकनीकी शाखा प्रवेश (एसएसबी इंजीनियरी) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

(क) **कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारक. डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध सीपीएल रखने वाले उम्मीदवार और **01 जनवरी 2001 से 01 जनवरी 2007 (दोनों तिथियां मिलाकर)** के बीच पैदा हुए उम्मीदवार पैरा 2(ख) में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार पायलट प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं.

(च) एनसीसी उम्मीदवार. एनसीसी 'ग' प्रमाणपत्र धारकों को निम्नलिखित मानदंड को पूरा करने पर एसएसबी के लिए लघुसूचीकरण के लिए कट ऑफ अंकों में 5% की छूट दी जाएगी:

(i) न्यूनतम 'ख' ग्रेड के साथ नौसेना/सेना/वायु विंग का एनसीसी 'ग' प्रमाणपत्र.

(ii) एनसीसी के वरिष्ठ प्रभाग, नौसेना/सेना/वायु विंग में दो अकादमिक वर्ष से अधिक की सेवा दी हो.

(iii) 'ग' प्रमाणपत्र 01 जनवरी 2023 से पूर्व की तिथि का नहीं होना चाहिए.

नोट (2): अंतिम चयन, उसकी वैधता के लिए डीजीएनसीसी/संबंधित एनसीसी द्वारा प्रमाणपत्र के सत्यापन पर होगा. उम्मीदवार की उम्मीदवारी को गलत घोषणा, गलत जानकारी या जानकारी छिपाने के मामले में चयन/प्रशिक्षण/पोस्ट कमिशनिंग के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी.

3. कौन आवेदन कर सकता है?

- उम्मीदवार, जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर की है या कुल में न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष सीजीपीए के साथ अंतिम वर्ष में हैं.
- उक्त उल्लिखित के लिए विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम, 1956; आईआईटी अधिनियम, 1961; एआईसीटीई अधिनियम,1987; एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007; आईआईआईटी अधिनियम 2014 के अधीन भारत में केन्द्र या राज्य लेजिस्लेचर अधिनियम या संसद अधिनियम द्वारा स्थापित या मानित विश्वविद्यालय/स्वयत्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षिक संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए.

या

- उम्मीदवार जिन्होंने ऐसी विदेशी विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्था से कुल में 60% अंकों या समकक्ष सीजीपीए/सिस्टम के साथ इंजीनियरी में डिग्री प्राप्त की है.
- विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्था को अद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त होना चाहिए या एआईयू अधिनियम 1973 के अधीन स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय संघ से इंजीनियरी डिग्री/समकक्ष प्रमाणपत्र धारक आवेदन कर सकते हैं.

नोट (3): (क) उम्मीदवार को जनवरी 2026 में आईएनए, एझिमाला से जुड़ने से पहले उक्त निर्धारित शैक्षिक योग्यता को पूरा करना होगा.

(ख) निर्धारित शैक्षिक मानदंड को पूरा ना करने पर उम्मीदवार को आईएनए, एझिमाला से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी.

(ग) सभी एसएसबी संस्तुत उम्मीदवारों को 20 दिसंबर 2025 से पहले ईमेल आईडी **officer@navy.gov.in** पर भारतीय नौसेना की संबंधित डिग्री के उनके अंतिम परिणाम के बारे में सूचित करना होगा.

नोट (4) : (क) एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक आवेदन भरा जा सकता है.

(ख) सेवा अपेक्षा के आधार पर आधारित उम्मीदवारों की विशिष्ट संख्या, जिन्होंने एसएसी (पायलट) प्रवेश चुना है, उन पर एसएसबी/सीपीएसएस/विमानन चिकित्सा परीक्षा के लिए विचार किया जाएगा और इस विकल्प का चयन करने से पूर्व इस प्रविष्टि के लिए शारीरिक/चिकित्सा मानक (ऊंचाई, पैर की लंबाई आदि) की जांच करने की सलाह दी जाती है. बाकि के उम्मीदवारों पर उनके द्वारा चुनी गई अन्य प्राथमिकताओं के लिए विचार किया जाएगा.

(ग) उम्मीदवारों को अन्य शाखाओं/काडर के लिए भी अपनी प्राथमिकता अंकित करनी होगी, यदि वे उन शाखाओं/काडर के लिए विचार किए जाने की इच्छा रखते हैं.

(घ) उम्मीदवारों पर उन शाखाओं/काडर के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिनका चयन नहीं किया गया है.

(ङ) प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को रुपये 31,250/- का पायलट/एनएओओ भत्ता स्वीकार्य होगा.

(च) उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता अंकित करने से पूर्व **लागू चिकित्सा मानकों** के संदर्भ में शाखाओं/काडर के लिए अपनी पात्रता निश्चित करने की सलाह दी जाती है.

(छ) उक्त पैरा 2(च), (छ), (ज) और (झ) में उल्लिखित के अलावा बीई/बी.टेक योग्यताओं के किसी भी समकक्ष स्ट्रीम पर किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया के लिए वैध विचार नहीं किया जाएगा.

4. चिकित्सा मानक/हाइट और वजन में छूट/टैट्: जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in** देखें. एसएसबी संस्तुत उम्मीदवारों को अपनी प्रविष्टि में लागू अनुसार चिकित्सा परीक्षा देनी होगी. **चिकित्सा अस्पताल/केन्द्र में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है.**

5. आयोग की अवधि: चयनित उम्मीदवारों को शुरू में 12 वर्ष के लिए लघु सेवा आयोग अनुदान दिया जाएगा जो सेवा अपेक्षा, निष्पादन, चिकित्सा पात्रता और उम्मीदवार की इच्छा पर अधिकतम 02 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है.

6. चयन प्रक्रिया: चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

क. आवेदन की लघुसूचीकरण, अर्हक डिग्री में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सामान्य अंकों के आधार पर किया जाएगा. अर्हक डिग्री में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को 'भारतीय नौसेना से जुड़ें' की वेबसाइट (**URL:- https://www.joinindiannavy.gov.in/files/normalisation.pdf**) पर उल्लिखित फॉर्मूले का प्रयोग करके सामान्य किया जाएगा.

ख. बीई/बी.टेक: उम्मीदवार, जिन्होंने बीई/बी.टेक पूर्ण कर लिया है या अंतिम वर्ष के पांचवें सेमेस्टर तक प्राप्त अंकों पर एसएसबी लघुसूचीकरण के लिए विचार किया जाएगा.

ग. स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम: उम्मीदवार जिन्होंने एमएससी, एमसीए,एमबीए, एमटेक पूर्ण कर लिया है उनके सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा. उम्मीदवार जो अंतिम वर्ष में हैं उनका लघुसूचीकरण पूर्व फाइनल वर्ष निष्पादन के आधार पर किया जाएगा.

घ. अंतिम योग्यता सूची में चयनित उम्मीदवारों को **officer@navy.gov.in** पते पर ईमेल भेजकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ अर्हक डिग्री पूर्ण करने के प्रमाण को जमा करना होगा. मानदंड को पूरा ना करने वाले उम्मेदवारों को अकादमी से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी.

ङ. लघुसूचीबद्ध उम्मीदवारों को ईमेल या एसएमएस (उनके आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए) द्वारा एसएसबी साक्षात्कार के लिए उनके चयन के बारे में सूचित किया जाएगा. उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक अपना **ईमेल/मोबाइल नंबर ना बदलने** और अपने इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर को समय-समय पर देखते रहने की सलाह दी जाती है.

च. साक्षात्कार के लिए एसएसबी केन्द्र में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

छ. एसएसबी तिथियों में परिवर्तन संबंधी कोई भी पत्राचार, बुलावा पत्र प्राप्त होने पर संबंधित एंसएसबी के कॉलअप अधिकारी को भेजा जाएगा. उम्मीदवारों को एसएमएस/ईमेल (उनके आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिया गया) द्वारा नौसेना मुख्यालय से सूचना प्राप्त करने पर बुलावा पत्र डाउनलोड करना होगा.

ज. एसएसबी साक्षात्कार के दौरान परीक्षाओं के परिणामस्वरूप लगी किसी भी चोट के मामले में कोई भी मुआवजा स्वीकार्य नहीं है.

झ. यदि आयोग के विशेष प्रकार के लिए पहली बार प्रस्तुत हो रहे हैं तो एसएसबी साक्षात्कार के लिए एसी 3 टियर का रेल किराया स्वीकार्य है. उम्मीदवारों को एसएसबी के लिए प्रस्तुत होते समय, पास बुक या चेक लीफ जहां नाम, अकाउंट संख्या और आईएफएससी विवरण उल्लिखित हैं, उसके पहले पेज की फोटोप्रति लानी होगी.

ञ. एसएसबी प्रक्रिया का विवरण भारतीय नौसेना की वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in** पर उपलब्ध है.

7. योग्यता सूची. रिक्तियों की उपलब्धता और संबंधित प्रवेश के लिए चिकित्सा अनापत्ति के अनुसार सभी प्रविष्टियों के लिए एसएसबी अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी. चिकित्सा परीक्षा में स्वस्थ घोषित उम्मीदवारों को प्रविष्टि में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नियुक्त किया जाएगा.

8. प्रशिक्षण. क. उम्मीदवारों को रिपोर्ट करने के बाद आईएनए, एझिमाला में इनडक्शन चिकित्सा परीक्षा पास करने पर सब लेफ्टिनेंट के ओहदे में नियुक्त किया जाएगा.

ख. केवल अविवाहित उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं. कोई भी उम्मीदवार विवाहित पाया जाता है या प्रशिक्षण के दौरान विवाह करता है तो उसे सेवा से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे उसके द्वारा आहरित पूर्ण वेतन और भत्ते और सरकार द्वारा उम्मीदवार पर किए गए अन्य खर्च की लौटाना होगा.

ग. यदि अधिकारी स्वेच्छा से आरंभिक प्रशिक्षण से वापसी करता है या परीक्षीक्षा अवधि के दौरान त्यागपत्र देता है तो उसको पूरी या अंश में प्रशिक्षण की लागत, जैसे सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और सरकार से वेतन और भत्ते के रूप में उसके द्वारा प्राप्त सारी राशि को सरकारी लोन के लिए प्रचलित दर पर आंकी गई कथित राशि पर ब्याज के साथ वापस करना होगा.

9. परिवीक्षा अवधि: एसएसबी अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि (एनएआईसी) तीन वर्ष है और अन्य शाखाओं/काडर के अधिकारियों के लिए दो वर्ष है. परिवीक्षा अवधि सब लेफ्टिनेंट के ओहदे के अनुरान की तिथि से शुरू होगी और एसएसबी (एनएआईसी) के लिए तीन वर्ष के बाद समाप्त होगी और अन्य शाखाओं/काडर के लिए दो वर्ष या आरंभिक प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर (जो भी बाद में हो). परिवीक्षा के दौरान अधिकारियों को किसी भी स्तर पर असंतोषजनक निष्पादन के मामले में सेवामुक्त किया जा सकता है.

10. वेतन और भत्ते/समूह बीमा और ग्रेच्युटि/छुट्टी हकदार/अधिकारियों की ड्यूटी: सब लेफ्टिनेंट का आरंभिक कुल वेतन रुपये 1,10,000/- (लगभग) प्रति माह के साथ लागू अनुसार अन्य भत्ते हैं. अधिक विवरण भारतीय नौसेना की वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in** पर उपलब्ध है.

11. आवेदन कैसे करें: उम्मीदवार भारतीय नौसेना की वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in** पर रजिस्टर करें और आवेदन भरें. आवेदन जमा करने की विंडो के दौरान समय बचाने के लिए उम्मीदवार पहले से अपना विवरण भर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. आवेदन को ऑनलाइन जमा निम्नानुसार किया जाए:

क. ई-आवेदन भरते समय, निम्नलिखित को करने के लिए संबंधित दस्तावेजों को आसानी से उपलब्ध रखने की सलाह दी जाती है:

(I) निजी विवरण को सही से भरें. विवरण, मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार भरा जाए.

(II) फील्ड जैसे ईमेल पता, मोबाइल नंबर अनिवार्य फील्ड हैं और भरे जाने हैं.

ख. आवेदन भरते समय नियमित और एकीकृत बीई/बी.टेक पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 5वें और 7वें सेमेस्टर तक और अन्य डिग्री परीक्षा के लिए सभी समेस्टर की अंकतालिकाएं, संबंधित दस्तावेज (भूल में प्रमुखता), जन्मतिथि प्रमाण (10वीं और 12वीं प्रमाणपत्र के अनुसार), बीई/बी.टेक के लिए सीजीपी, कन्वर्जन फार्मूला, भारत सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी मर्चेंट नौसेना प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स द्वारा जारी एनसीसी 'ग' प्रमाणपत्र और एक हाल के पासपोर्ट आकार कलर फोटो को संलग्न किए जाने के लिए मूल जेपीजी/टीआईएफएफ प्रारूप में स्कैन किया जाना चाहिए.

ग. यदि कोई भी स्कैन किया गया दस्तावेज किसी भी कारण से पाठ्य नहीं है तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को आवेदन का प्रिंटआउट लेना होगा और इसे एसएसबी साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होते समय साथ लाना होगा.

घ. एक बार जमा किया गया आवेदन अंतिम होगा और संशोधन/परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

नोट (5): क. अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले कृपया वेबसाइट पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें.

ख. यदि चयन के किसी भी स्तर पर कोई भी घोषणा गलत पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा.

ग. नशीले पदार्थों का प्रयोग/पास रखना प्रतिबंधित है. एसएसबी चयन/चिकित्सा/प्रशिक्षण के दौरान और बाद की सेवा के दौरान शरीर में नशीले पदार्थों के होने के लिए उम्मीदवार की जांच की जा सकती है. यदि चयन/चिकित्सा/प्रशिक्षण/सेवा के दौरान उम्मीदवार के नशीले पदार्थों का प्रयोग किए जाने/पास में पाया जाता है तो उम्मीदवार को भारतीय नौसेना से निकाल दिया जाएगा या यदि पहले से जुड़ जाते हैं तो सेवा से निकाल दिया जाएगा.

घ. आपके आवेदन को बाद में जांचा जाएगा और यदि किसी भी समय आवेदन अपात्र/अवैध पाया जाता है, तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा.

(नोट: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें.)

BM Group of Colleges

Recognized and approved by AICTE/ BCI/NCTE (New Delhi) & DTE /DHE (Bhopal)
Affiliated To Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore & RGPV, Bhopal

REQUIREMENTS

(Under College Code 28)

Principal / Professor / Associate Professor / Assistant Professor / Librarian / Sports Officer

REQUIRED FOR COURSES - MBA, BBA, B.Com., B.Sc., B.Ed., B.A. LL.B.(Hons), LL.B (Hons), BCA, In the Subjects Management/ Commerce / Seed Technology / Bio-Technology / Physics / Chemistry / Maths / Computer Application / English / Hindi / Education / Law Eligibility as per UGC / BCI / AICTE / NCTE and State Govt. Norms

BM College of Technology (MBA Deptt.) | BM College of Management & Research | BM Institute of Professional Studies | BM Professional Institute

Apply within 7 days at: **info@bmcollege.ac.in**
Campus : Near Chokhi Dhani, Khandwa Road, Indore

R-50583/2025

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, पुलिस लाइन रीवा (म.प्र.)
फोन नं. : 9425601556/9340714903

प्रेस-विज्ञप्ति

संभाग रीवा के अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण कार्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निवाड़ी जिला निवाड़ी के कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 11/2024-25 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक **MPPHCL/TENDER NO. 2025_MPPHC_402348_1** आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2025 समय 17:00 बजे तक ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/118790/2025	R-50588/2025	**परियोजना यंत्री**

पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल

क्र. 258-2/2025	**शहडोल, दिनांक : 10.02.2025**

विज्ञापन सूचना

चतुर्थ दीक्षांत समारोह में टेंट एवं विद्युत व्यवस्था संबंधी निविदा MP E-Tender पोर्टल पर निविदा क्रमांक 2025_PSNSU_397563/3 प्रकाशित की गई है।

आर-50581/2025	**कुलसचिव**

पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल

क्र. 258-1/2025	**शहडोल, दिनांक : 10.02.2025**

विज्ञापन सूचना

चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भोजन सामग्री प्रदाय किये जाने संबंधी निविदा MP E-Tender पोर्टल पर निविदा क्रमांक 2025_PSNSU_397524/2 प्रकाशित की गई है।

आर-50580/2025	**कुलसचिव**

SAINIK SCHOOL REWA (M.P.)

(Functioning under Sainik Schools Society, New Delhi)

CORRIGENDUM - EXTENSION OF LAST DATE OF RECRUITMNT OF STAFF (CONTRACTUAL BASIS)

Please refer to advertisement published in Employment News, New Delhi dated 11-17 Jan 2025 & Rojgar Aur Nirman, Bhopal dated 06-12 Jan 2025 for the Post of PGT English (Contractual)-01 for OBC-NCL, PGT Biology (Contractual)-01 for OBC-NCL & Counsellor (Contractual)-01 for Unreserved. Last Date for Submission of Application in prescribed format has been extended upto **10 Mar. 2025.** Please visit school website **www.sainikschoolrewa.ac.in** for detailed info.

R-50579/2025	**Principal, Sainik School, Rewa**

INTELLICON COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES

Plot No. 751.1,764/2/1, 765/1, 778 Gram Kharpa, Ratibad, Bhopal (M.P.)
Recognized by NCTE, And Affillated to Barkatullah University, Bhopal (M.P.)

Applications are invited for the appointment of Teaching staff for B.Ed. Programme under college code-28 of the University

PROFESSORS /ASSISTANT PROFESSORS

In science, Social Science, Arts / Humanities, Commerce, Language, Fine Arts, Performing arts and Physical Education. Qualifications and salary as per NCTE/UGC/ Affiliating University. Interested candidate may send their resume along with all the documents and passport size photograph or mail to **intellicon123@gmail.com** within 7 days.

JYOTI

R-50597/2025

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT COR. LTD.

(A Government of M.P. Undertaking)
Regional Office, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.), Phone : (O) +91755-2420301-2-3
Date : 10.02.2025

NOTICE INVITING TENDER FOR YEAR - 2024-25

Online Tender for the following works are invited on the E-procurement System portal **mptenders.gov.in** as detailed below :

NIT No.	Subject	Probable amount of Contract (In Lakhs)
12	Proposed Interior & Furniture work at MPIDC Office at Narmadapuram, Distt. Narmadapuram (M.P.)	48.33
13	Repairing of filter, replace of filter media, clarifier bridge and civil work etc complete of 05 MGD WTO at Industrial Area Mohasa, Distt. Narmadapuram (M.P.)	34.54

Detailed NIT along with other details can be downloaded/ viewed on above mentioned portal from 11.02.2025 10:30 Hrs.

M.P. Madhyam/118750/2025	**EXECUTIVE ENGINEER**

R-50586/2025

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

Government of Madhya Pradesh Undertaking
Regional Office, Indore, 101, First Floor, ATULYA IT Park, Near Crystal IT Park Khandwa Road, INDORE- 452007 (M.P.)
Phone : (O) 2970611, 2971311, 2974363, Fax No. : 0731-2972629, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in
Website : www.invest.mp.gov.in, GSTN : 23AACCM6080D2ZT, CIN : U45203MP1981SGC001850

No. MPIDC/R.O./IND/Tech/2025/1385	**Date : 10.02.2025**

NOTICE INVITING TENDER

Tender for the following works have been proceeded on the e-procurement system - **http:// www.mptenders.gov.in** as mention below-

S.No.	Name of work	PAC (Rs. in Lakh)	Cost of tender form	EMD
1	Construction of miscellaneous works at Industrial area Electronic complex, Indore.	Rs. 153.00 lakh	Rs. 14750/- i/c GST	Rs. 153004/-

The Detailed NIT and tender documents can be viewed and purchased after publication in newspaper within 7 working days from website - **http://www.mptenders.gov.in**

M.P. Madhyam/118752/2025	R-50587/2025	**EXECUTIVE ENGINEER**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना क्रमांक 24/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2024-25	**भोपाल, दिनांक : 10.02.2025**

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. कार्य का नाम 1. :- नर्मदापुरम जिले में राजमार्ग 67 कन्हवार पुनोर मार्ग में इटारसी जबलपुर रेलखण्ड के लेवल क्रॉसिंग क्रमांक-239 रेलवे कि.मी. 823/5-7 पर रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु।
2025_ PWDRB_ 401735_1	नर्मदापुरम	पुल कार्य	तृतीय	2098.00	केवल ऑनलाइन
			कुल योग	**2098.00**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 03.03.2025 (17:30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता
जी-22958/50582/2025	**लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र, भोपाल**

वर्चुअल टूर से मिलेगी मध्यप्रदेश के इतिहास और संस्कृति की जानकारी

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड और फिनलैंड की संस्था वी रियल के बीच प्रदेश के पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और संग्रहालयों पर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर वर्चुअल टूर तैयार करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवंत अनुभूति देने वाले इन वर्चुअल टूर के माध्यम से अब पर्यटन, इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले व्यक्ति, अपने देश में रहते हुए मध्यप्रदेश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। इससे प्रदेश के पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने में मदद मिलेगी और विश्व के विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि फिनलैंड की कंपनी वी-रियल द्वारा इतिहास, संस्कृति, और धरोहर का उन्नत तकनीक के माध्यम से वीडियो निर्माण कर संरक्षित और पुनर्जीवित किया जाता है। कंपनी इस वर्चुअल टूर को अपने प्लेट फार्म पर उपलब्ध कराती है, जो वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं सहित टूर और ट्रैवल संस्थानों सहित आम नागरिकों के लिए उपलब्ध रहते हैं।

VACANCIES

■ Principal ■ Asso. Professor ■ Asst. Professor

For : Computer Science, Computer Application, Maths, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Microbiology, Biotechnology, Life Science, Seed Technology, Horticulture, Statistics, Management, Hindi Language, English Language, Commerce, Economics, Political Science

Salary & Qualification As per UGC Norms
Whatsapp / Mail or post application along with a recent Passport Photograph within 07 days

SARDAR VALLABH BHAI PATEL COLLEGE, MANDLESHWAR
Barwaha Road Mandleshwar, Dist. - Khargone (M.P.)
Mob. 7898766231, 9131108889, 89899 38484, 8319637270
E-mail : svpcmdlresume@gmail.com

MEHTA

R-50598/2025

IPS ACADEMY
COLLEGE OF LAW - SANWER

***Forward Thinking Campus* : Indore - Ujjain Road**

Approved by BCI, Higher Education of MP & Affiliated to DAVV, Indore

REQUIRED
Under College Code 28

Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor
(Law - 06, History - 01, English - 01, Political Science - 01, Economics - 01) For

BA.LL.B(Hons.) & LL.B(Hons.)

Eligibility & Pay Scale : As per BCI & UGC Norms.
Apply within 7 days with complete CV and testimonials to **ipsahr.sanwer@ipsacademy.org**

Indore - Ujjain Road. Vill. Barodiya Khan, Indore-453551, (MP)
M.No. 6262604161

Adcom

Director- IPSA

R-50584/2025

प्रयागराज महाकुंभ जा रहे यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं बनाए रखें

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संभाग अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में मध्यप्रदेश से जा रहे श्रद्धालुओं को सुगम वातायात, रहने और भोजन सहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रबंधों की जिलेवार जानकारी भी ली। उन्होंने निर्देश दिए की महाकुंभ की अवधि तक आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने देह दान करने वाले व्यक्तियों का राजकीय सम्मान करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखने के संबंध में रीवा, सीधी, गैहर, सतना, मऊगंज जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यक प्रबंध रखने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा से चर्चा में शामिल हुए।

आपदा प्रबंधन अच्छा हुआ है

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा जी में स्नान और दान पुण्य के कार्य शुभ माने गए हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डॉ. यादव ने कहा कि जिले के प्रशासनिक अमले ने कुशलतापूर्वक आपदा प्रबंधन कार्य किया है। आने वाले दिनों में भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई रखी जाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का पूरा सहयोग प्राप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री को दूरदर्शिता के लिए जनप्रतिनिधियों ने दिया धन्यवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में रीवा संभाग के जिलों में महाकुंभ के लिए जा रहे यात्रियों को सुविधाएं देने के निर्देश दिए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में रीवा संभाग के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दूरदर्शिता और कार्यशैली की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 29 जनवरी को प्रयागराज में तीर्थयात्रियों की संख्या पहली बार बढ़ने पर उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती जिलों में रैन बसेरे सहित भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य अच्छी तरह संपन्न हुआ। इन व्यवस्थाओं से आपदा की स्थिति नहीं बनी। वाहनों को होल्ड पर रखने और क्रमशः रवाना करने की व्यवस्था रीवा संभाग सहित जबलपुर संभाग के जिलों में भी की गई।

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश

- प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
- चित्रकूट में भी यात्रियों के रहने और भोजन की व्यवस्था की जाए।
- मैहर एवं स्थानीय धार्मिक महत्व के स्थानों पर भी आवश्यक प्रबंध के लिए सामाजिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जाए।
- अधिक संख्या में जा रहे श्रद्धालुओं की स्थिति को देखते हुए समाधान निकालें। आवश्यक हो तो कंट्रोल रूम बनाएं। इस कार्य में ढिलाई ना बरती जाए।
- यात्रियों के लिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध रहे।
- पूर्व में किए गए प्रबंध संतोषजनक हैं। आगे भी ऐसे ही प्रबंध प्रयागराज महाकुंभ के पूर्ण होने तक जारी रहें।

मुख्यमंत्री ने पीपलरावां में किया विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

हमारी सरकार का संकल्प है हर हाथ को काम, हर खेत को पानी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के पीपलरावां गांव में आयोजित समारोह को संबोधित किया

देवास, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास के सोनकच्छ के ग्राम पीपलरावां से एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रुपये, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ रुपये और 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित किये। उन्होंने कार्यक्रम में 144.84 करोड़ रुपये लागत के 53 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रंजीत सागर परियोजना से आस-पास के गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। क्षेत्र में हरियाली छायेगी और किसान समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पारस पत्थर से लोहा भी सोना बन जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत को पानी और बिजली की सुविधा मिले तो किसान समृद्धशाली होंगे और

- समाज में मां, बहन और बेटियों का सर्वोच्च स्थान।
- हमारा काम है हर व्यक्ति की जिंदगी बेहतर बनाना।
- इस बार किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य होगा 2600 रुपये।
- 27 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में अंतरित किए 1553 करोड़ रुपये।
- जल कलश यात्रा का किया समापन।

फसलरूपी सोना जरूर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और बिजली उपलब्ध करा रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 वर्ष पहले जो नदी जोड़ो का सपना देखा था अब वह प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हमें केन-बेतवा लिंक योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए हैं। इस योजना से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। एक अन्य 70 हजार करोड़ रुपये की पार्वती-कालीसिंध-चंबल योजना पर भी कार्य शुरू हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक गांव के एक-एक खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट कर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देकर दुनिया में भारत का मान बढ़ाना और मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना हमारा उद्देश्य है।

देश में चल रहा है सांस्कृतिक अनुष्ठान

प्रयागराज, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ मेले में विक्रमादित्य नाटक का मंचन देखा। उन्होंने इस नाटक के मंचन को अद्भुत प्रसंग बताया। डॉ. यादव ने शानदार नाट्य प्रस्तुति के लिए कलाकार दल को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान चल रहा है। डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने भगवान श्रीराम का आशीर्वाद प्राप्त किया था। सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार की पहल की थी।

इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को शीघ्र क्रियान्वित करें

भोपाल, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मध्यप्रदेश में सड़क और भवन परियोजनाओं के सुचारू संचालन और पारदर्शी निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। श्री सिंह ने कहा कि आईपीएमएस के प्रथम चरण को फरवरी 2025 के अंत तक, द्वितीय चरण को मई 2025 तक और तृतीय चरण को जुलाई 2025 तक पूर्ण किया जाए। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट मार्च 2025 में सचिवालय स्तर पर आईपीएमएस के माध्यम से ही संसाधित किया जाए।

गत वर्ष लोक निर्माण विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मंत्री श्री सिंह ने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अगस्त 2024 को इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि आईपीएमएस एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से निर्माण कार्यों की मांग से लेकर स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया, क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और परफॉर्मेंस गारंटी पूरी होने तक समस्त कार्यवाही ऑनलाइन होगी। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग और एमपी रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा सड़कों, पुलों और भवन परियोजनाओं के डिजिटल एवं पारदर्शी प्रबंधन के लिए विकसित की गयी एक अत्याधुनिक प्रणाली है, जिसकी अनुमानित लागत 17 करोड़ रुपये है।

इस प्रणाली में परियोजनाओं की योजना, निविदा प्रक्रिया, निर्माण, निरीक्षण, भुगतान और संपूर्ण मॉनिटरिंग को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और कार्य की गति में उल्लेखनीय सुधार होगा।

सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों की विभागीय कार्ययोजना एवं उससे जुड़े वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्ययोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में विभागों को जारी किए गए बजट में वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए शत-प्रतिशत बजट का उपयोग सुनिश्चित करें। नये वित्तीय वर्ष के बजट में योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं। सभी विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें, जिससे विकास कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आयुष्मान निरामयम योजना की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के प्रकरणों में तत्परता और सजगता से कार्रवाई की जाये। सभी पात्र व्यक्तियों के तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाये जायें।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाए। जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे।

जीआईएस से प्रदेश का इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा बूस्ट-अप - मुख्यमंत्री

भोपल, मध्यप्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भोपाल के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, बगरोदा, पीलूखेड़ी, गोविंदपुरा, अचारपुरा और फंदा के उद्यमियों के साथ ही उन युवाओं में भी खासा उत्साह है, जो नई तकनीक को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूर्ण करने में सहभागी बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने निवेश संबंधी अपने विदेश दौरे में कंपनियों को तकनीकी रूप से भी मध्यप्रदेश के विकास में सहभागी बनने का निमंत्रण दिया है। यूके, जर्मनी और जापान की कंपनियों ने तकनीक के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश को आगे बढ़कर संवारने का वादा किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जब विदेशी कंपनियां अपने उद्योग

यहां स्थापित करेंगी, तो निःसंदेह नवीनतम तकनीक यहां आएगी और उद्योगों को विश्व स्तरीय तकनीक के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे प्रदेश का इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट-अप भी होगा।

मुख्यमंत्री के नवंबर 2024 में हुए 6 दिवसीय यूके और जर्मनी दौरे में उद्योगपतियों और निवेशकों से लगभग 78 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। इससे प्रदेश के समग्र विकास और टेक्नो-फ्रेण्डली युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के यूके-जर्मनी दौरे से पहले सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रस्ताव आया था कि तकनीकी क्षेत्र में जर्मनी और भारत संयुक्त रूप से भोपाल के अचारपुरा में इकाई स्थापित करेंगे। इस कंपनी के जर्मन निवेशक को जर्मनी में भूमि आवंटन-पत्र प्रदान किया गया। कंपनी द्वारा भोपाल में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। सॉफ्टवेयर और आईटी पार्क के निर्माण पर विभिन्न इंटरैक्टिव सेशन और राउंड टेबल डिस्कशन भी संपन्न हुए हैं। वुडपैकर सॉफ्टवेयर ने रसायन और आईटी सेक्टर में 1,100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूके और जर्मनी की यात्रा से टेक्नो-फ्रेंडली युवाओं के लिए रोजगार सृजन के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन (जेट्रो) के अध्यक्ष श्री सुसुमु काताओका के साथ बैठक में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। जेट्रो मध्यप्रदेश में अपना कार्यालय स्थापित कर सकता है, जिससे जापानी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मध्यप्रदेश में वैश्विक टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार की हैं अपार संभावनाएं - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग में निवेश से जुड़ी जानकारी देते हुए

भोपाल, मध्यप्रदेश टेक्सटाइल और परिधान उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला राज्य बन गया है। राज्य की समृद्ध कृषि पृष्ठभूमि, पारंपरिक बुनकर समुदायों की उत्कृष्ट कला, आधुनिक औद्योगिक आधार और निवेशक अनुकूल नीतियां प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बना रही हैं। सरकार के प्रयासों से मध्यप्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंट हब के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 इस औद्योगिक यात्रा को और गति देने का माध्यम बनेगा, जहां दुनियाभर के निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा में दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, जिसमें कच्चे माल के उत्पादन से लेकर परिधान निर्माण और वैश्विक निर्यात तक सभी चरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश, भारत के 43 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर 24 प्रतिशत ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन में योगदान देता है। यह आंकड़ा न केवल प्रदेश की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि इसे पर्यावरणीय रूप से सतत और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र निर्माण के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।

- **प्रदेश में 60 से अधिक बड़ी कपड़ा मिल्स, 4,000 से अधिक करघे और 25 लाख स्पिंडल्स कार्यरत हैं।**
- **इंदौर का रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर 1,200 से अधिक इकाइयों के साथ प्रदेश में बना रेडीमेड वस्त्र निर्माण की प्रमुख इकाई।**

कपास, रेशम और आधुनिक फाइबर– मध्यप्रदेश की बुनियादी ताकत

डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी है। साथ ही यहां का रेशम उद्योग भी लगातार विस्तारित हो रहा है। राज्य प्रतिवर्ष 200 टन से अधिक रेशम उत्पादन करता है, जिससे परंपरागत हथकरघा और आधुनिक सिल्क उत्पाद दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश आधुनिक कृत्रिम फाइबर उत्पादन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पेशियलिटी फाइबर निर्माण को बल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक नीतियां लागू कर रही है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र में 3,513 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। यह निवेश प्रदेश को उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र निर्माण और निर्यात में अग्रणी बनाएगा। सरकार उद्योगों को बिजली और पानी न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवा रही है। साथ ही, जीएसटी में छूट, टैक्स रिबेट और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेशकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की समीक्षा कर पात्रों को लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

भोपाल, जनकल्याण ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। योजनाओं के जरिए ही हम इस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। प्रदेश के विकास में हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंद हितग्राहियों को पात्रतानुसार त्वरित लाभ दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के तय लक्ष्यों की समय पर पूर्ति की जानी चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रतिदिन समीक्षा की जाए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ पाने से न छूटे। हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सभी विभाग अपने स्तर पर सतत समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा और विलम्ब के समय पर हितग्राहियों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाएं सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही जनता को शासन की संवेदनशीलता का अनुभव होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का फुल सैचुरेशन किया जाना है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

साथ ही बैंकों द्वारा वित्तपोषित योजनाओं में हितग्राहीमूलक प्रकरणों को निर्धारित समय से पहले लक्ष्य से भी कहीं ज्यादा संख्या में प्रस्ताव भेजे जाएं, ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हो रहा है प्रभावी क्रियान्वयन

भोपाल, प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष-2020 का स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में अध्यायवार राज्य स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है। अधिकारियों, प्राचार्यों और शिक्षकों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर केन्द्रित ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्रेकर के साथ क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

प्रदेश में वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के आधार पर 4473 शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इन शालाओं में आयु वर्ग समूह 3 से 6 के लगभग एक लाख बच्चे दर्ज हैं। शालाओं में उपलब्ध अतिरिक्त शिक्षक और कक्षा-1 और 2 को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पीएम पोषण उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से संबंधित 170 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित किये गये हैं।

परम वैभव की पुनर्प्राप्ति के लिए स्वत्व का भाव आवश्यक - उच्च शिक्षा मंत्री

भोपाल, भारत का इतिहास गौरवशाली, शौर्य और ज्ञान से समृद्ध रहा है। सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज की दूरदर्शितापूर्ण नीतियां, प्रबंधन और पुरुषार्थ भारत के गौरवशाली इतिहास को परिलक्षित करते हैं। उन महापुरुषों के कालखंड में नैतिक सत्ता हुआ करती थी। भारतीय इतिहास में परमार वंश की व्यापक प्रतिष्ठा थी। काल के प्रवाह में प्रतिष्ठा को विलोपित करने का षड्यंत्र रचा गया। समाज की प्रतिष्ठा को पुनः विश्वमंच पर स्थापित करने के लिए सामाजिक चेतना के स्वाभिमान के साथ जागरण की आवश्यकता है। समाज के महापुरुषों के पुरुषार्थ को समझकर उनके जीवन आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात् करना होगा। ये बातें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल स्थित गुफा मंदिर के मानस भवन में 'राजा भोज पंवार (परमार) समाज संगठन भोपाल' के स्नेह सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में कहीं।

श्री परमार ने समाज के ऐतिहासिक परम वैभव की पुनर्प्राप्ति के लिए स्वत्व के भाव के साथ सामाजिक चेतना जागृति के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। श्री परमार ने कहा कि सनातन समाज को कभी किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारा समाज प्रकृति पूजक एवं सूर्य उपासक रहा है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और ऊर्जा स्रोतों को संरक्षण के लिए कृतज्ञता के भाव के साथ परंपराओं और मान्यताओं से समृद्ध किया।

गरीब कल्याण ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनैतिक दलों की दिशा और विचार प्रक्रिया निर्धारित की। साम्यवाद और पूंजीवाद के संघर्ष के उस दौर में उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और अंत्योदय की अवधारणा के माध्यम से यह स्थापित किया कि गरीब की भलाई ही सत्ता की सर्वोच्च प्राथमिकता हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस विचार का अनुसरण करते हुए गरीबों को नि:शुल्क अन्न, पक्के मकान, बच्चों की बेहतर शिक्षा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की। राज्य सरकार पं.दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना हमारा उद्देश्य है। प्रदेश में आरंभ की गई पीएमश्री एयर एंबुलेंस सुविधा का लक्ष्य हर गरीब और जरूरतमंद को आवश्यक इलाज उपलब्ध कराना है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थल पर नगर निगम भोपाल द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही नमो वन वाटिका का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 417 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया, जिसमें अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये लागत की सीवरेज परियोजना, तीन करोड़ रुपये की लागत से क्रय चार सीवर कम जैटिंग मशीनों और बस स्टाप के रूप में परिवर्तित की गई पुरानी बसों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के माध्यम से प्रदेश औद्योगिकरण की दिशा में नई उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है।

गरीब परिवारों के लिए वरदान है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

रीवा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान है। रीवा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 362 जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे। श्री शुक्ल ने कहा कि यह सरकार गरीबों, किसानों, बेटियों और युवाओं की सरकार है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा 18 लाख रुपये खर्च किए गए हैं तथा प्रत्येक जोड़े को 49 हजार रुपये के मान से लगभग एक करोड़ 75 लाख रुपये बेटियों को दिए जा रहे हैं।

वंचित वर्ग के व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर हिंदी भवन में आयोजित समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, गरीबों की गरीबी दूर हो, युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों का मान बढ़े और सभी लोग बराबरी से रहें, राज्य सरकार इस उद्देश्य से हर वर्ग के लिए योजनाएं और कार्यक्रम संचालित कर रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में दी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जीवन की कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री बने। उनसे यह प्रेरणा मिलती है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समाज को शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार और समानता का अधिकार दिया। जन-जन को इन सब अधिकारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'सबका साथ-सबका विकास' की अवधारणा के साथ समाज के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। राज्य सरकार उनके मार्गदर्शन में इस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश ही नहीं देश में सभी को यह अनुभूति है कि मध्यप्रदेश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रदेश के सामान्यजन की मेहनत का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर में संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य स्मारक आकार ले रहा है।

मध्यप्रदेश बनेगा ड्रोन निर्माण हब - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को ड्रोन निर्माण और प्रौद्योगिकी का प्रमुख हब बनाने के लिए समग्र कार्ययोजना तैयार की गई है। राज्य सरकार ने ड्रोन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी भी बनाई जायेगी।

ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी विभिन्न विभागों के मध्य परस्पर डेटा साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देगी। यह नीति जीआईएस आधारित योजना और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके बेहतर निगरानी तंत्र विकसित करेगी। यह रिपॉजिटरी तत्काल अद्यतन निगरानी सुविधा प्रदान करेगी, जिससे संसाधनों का त्रुटिरहित आवंटन होगा और अधोसंरचनात्मक विकास में सहयोग मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा प्रबंधन सुरक्षित रूप से किया जाए और सहयोगी भागीदारों के साथ रिपॉजिटरी की प्रबंधन व्यवस्था पुख्ता रखी जाए। राज्य की एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सभी ड्रोन डेटा को राष्ट्रीय भौगोलिक नीति-2022 या उसके बाद के किसी संशोधन या नीति के अनुसार डेटा सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अंतर्गत संग्रहित किया जाए। संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षित डेटा भंडारण और प्रसारण प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जायेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में

औद्योगिक संवर्धन नीति सहित अनेक नीतियां स्वीकृत

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 की स्वीकृति दी गयी है। इसके अंतर्गत 10 सेक्टर विशिष्ट नीतियों यथा कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति, परिधान, फुटवियर, खिलौने और सहायक उपकरण नीति, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति, मेडिकल डिवाइसेस नीति, ईज्ड विनिर्माण नीति, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति और हाई वेल्यू-एड विनिर्माता नीति को स्वीकृति दी गयी है।

औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य की वर्तमान जीडीपी को 2.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपये करने में उद्योगों का योगदान बढ़ाना है।

मध्यप्रदेश निर्यात नीति-2025

प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'मध्यप्रदेश निर्यात नीति-2025' लागू करने की स्वीकृति दी गयी। यह नीति निर्यात अधोसंरचना में निजी डेवलपर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए, निर्यात क्षेत्रों के डेवलपर्स को प्रोत्साहित करती है। नीति अतर्गत प्रावधानित अन्य गैर-वित्तीय सहायता एवं आईसीडी को सुगम बनाने के निर्णयों से प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नीति का उद्देश्य राज्य में बड़े निर्यातकों की भागीदारी में वृद्धि करना, निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना, निर्यात मात्रा और निर्यात दक्षता बढ़ाना, प्रदेश में निर्यातोन्मुखी इकाइयों को उनके निर्यात मूल्य को बढ़ाने में सहायता करना, विश्व स्तर पर 'मेड इन मध्यप्रदेश बाजार को विकसित करना और प्रदेश में रोज़गार के अवसर को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

'मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025' की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में लॉजिस्टिक अधोसंरचना विकसित करने और समग्र विकास के लिए मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। नीति का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष धारणीय, विश्वसनीय एवं अनुकूल लॉजिस्टिक अधोसंरचना का विकास करना और वर्ष 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप लॉजिस्टिक लागत को कम करना एवं डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र स्थापित करना है। लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउस अधोसंरचना अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो और ड्राय पोर्ट्स् की स्थापना के लिए निवेश सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क की सुविधा 25 एकड़ से 75 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने पर अधिकतम 50 करोड़ रुपये और 75 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर विकसित करने पर अधिकतम 75 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।

मध्यप्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नेटवर्क विकास नीति

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी नेटवर्क के विस्तार के लिए मध्यप्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, 2025 लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है जहां सीजीडी पॉलिसी लागू की जा रही है। मध्यप्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी नेटवर्क के अंतर्गत घरेलू उपयोग के लिए, वाणिज्यक एवं औद्योगिक इकाइयों में पाइप लाइन के माध्यम से पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति की जायेगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नेटवर्क का उद्देश्य घरों और उद्योगों के लिये स्वच्छ और किफायती ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। सीएनजी गैस स्टेशन के माध्यम से वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी की आपूर्ति की जायेगी।

पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है। साथ ही पर्यटन स्थलों में विश्वस्तरीय अधोसंरचना का निर्माण कर पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान कराना है। नीति के अंतर्गत गोल्फ, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसोर्ट, क्रूज, अंतर्प्रदेशीय वायु सेवा, हेरिटेज होटल, रोप-वे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो आदि के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। नीति अंतर्गत अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कलेक्टर गाइडलाइन दर पर 90 वर्षों के लिए उपलब्ध विभागीय भूमि का सीधा आवंटन किया जायेगा।

- युवाओं के लिये रोज़गार क्रांति साबित होंगी नीतियां।
- अगले पांच वर्षों में लगभग 20 लाख रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- इन नीतियों से निवेशकों की राह और आसान होगी।
- निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए 'मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति-2025' की स्वीकृति।

फैक्ट फाइल

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

एक वर्ष में 8.46 लाख परिवारों को मिला योजना का लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना को 13 फरवरी 2025 को एक वर्ष हो गया है। यह योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। इस योजना से हर घर में सूर्य से बिजली उत्पन्न हो रही है। इससे लोगों के बिजली के बिल में लगने वाले खर्च की बचत हुई है।

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कारण इस योजना से सौर क्रांति निर्मित हुई है। इस योजना का उद्देश्य छत पर पैनल लगाने की सुविधा देकर हर घर को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है। इस योजना से मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने का लक्ष्य प्राप्त होगा।

8.46 लाख परिवारों को मिला लाभ

27 जनवरी, 2025 तक, इस योजना से छत पर सौर ऊर्जा लगाने के माध्यम से 8.46 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की इस योजना को अपनाने में दस गुना वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभ

परिवारों के लिए मुफ्त बिजली- यह योजना सब्सिडी वाले छतों पर सौर पैनल लगाने के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में कमी आती है।

सरकार के लिए बिजली की लागत में कमी- सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने से, इस योजना द्वारा सरकार को बिजली की लागत में वार्षिक रूप से अनुमानित 75 हजार करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग- यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का निर्माण हो सके।

कार्बन उत्सर्जन में कमी- इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे भारत की कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभाव

घरेलू बचत और आय सृजन- घरों को अपने बिजली बिलों पर महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने रूफटॉप सोलर सिस्टम द्वारा उत्पादित अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित होगी।

सौर क्षमता का विस्तार- इस योजना से आवासीय क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से 30 गीगावॉट सौर क्षमता जुड़ने का अनुमान है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

पर्यावरणीय लाभ- इन छत प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवनकाल में, यह अनुमान लगाया गया है कि यह योजना 1000 बीयू बिजली उत्पन्न करेगी, तथा CO_2 उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी लाएगी, जिससे पर्यावरण पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

रोज़गार सृजन- इस योजना से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, संचालन और रखरखाव (O&M), और अन्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे देश में रोज़गार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

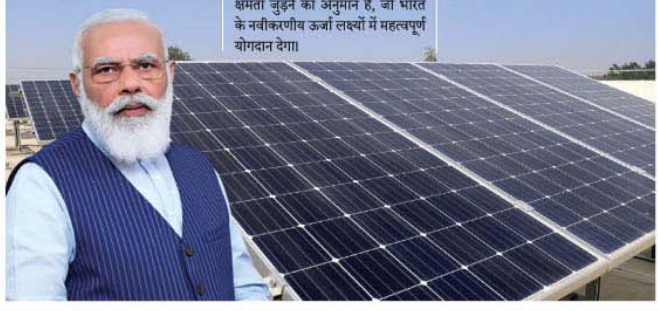

सब्सिडी कैसे प्राप्त करें

जब आपके घर सोलर प्लांट लग जायेगा और डिस्कॉम नेट मीटरिंग इंस्टॉल होने पर इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इसके बाद शासन द्वारा आपके अकाउंट में डीबीटी के तहत सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जायेगी।

योजना के लिये जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक।

आवेदन कैसे करें

इस योजना का लाभ लेने के लिये कंज्यूमर पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर कंज्यूमर नंबर, नाम, पता और कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगना है आदि जानकारियां भरनी होगी।

यह योजना 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे अक्षय ऊर्जा अधिक सस्ती और सुलभ हो जाती है। अब तक 5.54 लाख आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 4,308.66 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिसमें प्रति परिवार औसतन 77,800 रुपये की सब्सिडी है। इसके अतिरिक्त, अनुमानित 45 प्रतिशत लाभार्थियों को अब उनके सौर ऊर्जा उत्पादन और खपत पैटर्न के आधार पर शून्य बिजली बिल प्राप्त हो रहे हैं।

- शशांक मणि पांडे
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

चर्चा

शिखर धवन

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के इवेंट एंबेसडर बने

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए प्रतियोगिता दूत (इवेंट एंबेसडर) नियुक्त किया है। आईसीसी ने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए चार पूर्व क्रिकेटरों को इवेंट एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

डेविन गेराल्ड नून्स

ट्रंप के खुफिया सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेविन गेराल्ड नून्स को खुफिया सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बोर्ड में डेविन के सहयोग के लिए 11 अन्य लोगों की टीम भी होगी। ट्रंप ने डेविन को खुफिया सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के बाद कहा कि राष्ट्रपति के खुफिया सलाहकार बोर्ड में सेवा देने के लिए देशभक्तों के प्रतिष्ठित और भरोसेमंद समूह की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह बोर्ड देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों पर राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह देगा।

ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने

आईवीएफ से तैयार किया कंगारू का भ्रूण

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण बनाने में सफलता हासिल की गई है। यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पैट्रिसियो डी पैलेसियो और एंड्रेस गामबिनी ने हासिल की है। यह प्रयोग न केवल विज्ञान के लिए बड़ी उपलब्धि है बल्कि संकटग्रस्त मार्सुपियल प्रजातियों (स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई थैली में रखते हैं) के संरक्षण की दिशा में एक नई उम्मीद भी जगाती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इनके विलुप्त होने की दर बेहद चिंताजनक है।

इंस्टाग्राम ने

भारत में लॉन्च किया टीन अकाउंट

विश्व की दिग्गज टेक कंपनी मेटा ने बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए अपने फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में टीन अकाउंट नाम का एक नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर के जरिए बच्चों और टीनएजर्स को इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाली बुरी चीजों या किसी भी प्रकार के बुरे प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके। मेटा ने इंस्टाग्राम का टीन अकाउंट भारत में भी लॉन्च किया है। हालांकि, भारत में इस फीचर को फेज वाइज में रोलआउट किया जाएगा।

तुलसी गबार्ड

अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनीं

भारतवंशी तुलसी गबार्ड आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) बन गई हैं। वह मौजूदा निदेशक अवरील हेन्स की जगह लेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद तुलसी को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नामित किया था, अमेरिकी सीनेट में अंतिम मतदान के बाद तुलसी की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। सीनेट में 52 में से 48 सदस्यों ने तुलसी के पक्ष में मतदान किया। तुलसी अब अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की प्रमुख बन गई हैं। ये एजेंसियां देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम करती हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने

एक सेंट के सिक्के पर लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ऑर्डर जारी किया है। ट्रंप ने अमेरिका के कोषालय सचिव (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट को पेनी की ढलाई बंद करने का निर्देश दिया है। पेनी या एक सेंट अमेरिका में करेंसी की सबसे छोटी इकाई है। पेनी की ढलाई में होने वाले खर्च को देखते हुए यह फैसला किया गया है। एक पेनी की ढलाई में 3 सेंट खर्च होते हैं, यही वजह है कि काफी समय से इसे बंद करने की मांग उठ रही है। एक पेनी अमेरिकी डॉलर के 100वें हिस्से के बराबर होता है। अमेरिका में वर्ष 1857 में हाफ सेंट की ढलाई बंद हो गई थी और उसके बाद से पेनी यानी एक सेंट का सिक्का अमेरिकी करेंसी की सबसे छोटी यूनिट बनी हुई है।

स्मृति शेष

नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन

दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने वाले जननेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें नामीबिया का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नुजोमा के निधन की घोषणा नामीबिया के राष्ट्रपति नांगोलो म्बुम्बा ने की। उन्होंने कहा कि विंडहोएक के अस्पताल में नुजोमा ने अंतिम सांस ली। उन्होंने कहा कि नुजोमा ने हमारे मुक्ति संग्राम के सबसे संकट काल में नामीबियाई लोगों का नेतृत्व किया। वर्ष 1989 के अंत में संसदीय चुनावों में लौटने से पहले उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में 30 साल निर्वासन में बिताए।

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

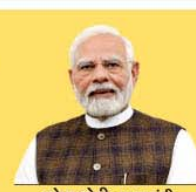
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रवेश प्रारंभ

"विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर बनाएं बेहतर भविष्य..."

संत शिरोमणि रविदास

ग्लोबल स्किल्स पार्क

(मध्यप्रदेश शासन का उत्कृष्ट संस्थान)

मुख्य विशेषताएं

- अत्यंत रियायती दर पर प्रशिक्षण शुल्क
- अत्याधुनिक प्रशिक्षण अधोसंरचना
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्नत पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यचर्या, उपकरण, ITEES सिंगापुर अनुसार
- जीवन कौशल प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग
- छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध
- छात्रावास सुविधा उपलब्ध
- एक छात्र एक मशीन का अनुपात
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार सहायता

98% प्लेसमेंट

एक-वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2025 के लिए

- एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी (पावर एंड कंट्रोल) (80 सीटें)
- एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल डिवाइस एंड IOT इंटीग्रेशन) (80 सीटें)
- एडवांस्ड नेटवर्किंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन (80 सीटें)
- एडवांस्ड एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन (80 सीटें)
- एडवांस्ड प्रिसीजन इंजीनियरिंग (120 सीटें)
- एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (40 सीटें)
- एडवांस्ड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी (40 सीटें)
- एडवांस्ड मेकाट्रॉनिक्स (40 सीटें)
- एडवांस्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेस (80 सीटें)

(अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 5%, अन्य राज्यों के छात्रों के लिए 20% और मध्यप्रदेश के छात्रों के लिए 75% सीट)

अधिक जानकारी के लिए स्केन QR

पात्रता : सम्बंधित संकाय में आईटीआई/इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण

प्रवेश : मेरिट के आधार पर

आरक्षण : एससी/एसटी/ओबीसी/35% महिला आवेदकों के लिए म.प्र. शासन के मापदंडों के अनुसार।

प्रवेश हेतु प्रारंभिक तिथि : 17 जनवरी, 2025, अंतिम तिथि : 15 मार्च, 2025

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क

हज़रत निज़ामुद्दीन कॉलोनी रोड, नरेला शंकरी, भोपाल (म. प्र.), admission.gsp@mp.gov.in

लैंडलाइन नंबर : 0755-2706205, 9981919733 | 9713992665 | 9893346258

इच्छुक आवेदक

https://admissions.globalskillspark.in पर आवेदन करें

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन

R-50589/2025

म.प्र. माध्यम/118799/2025

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र.
टेलीफोन नं. : 07522-234001, E-mail : datiamedicalcollege@gmail.com
Website : www.datiamedicalcollege.com
29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड-475661

क्रमांक-1321/स्था. राज./द.चि.म./2025 **दतिया, दिनांक :13.02.2025**

विज्ञप्ति सूचना

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-2-06/2018/1-55, दिनांक 07.04.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के अधीन निम्नलिखित आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा पूर्ति हेतु भर्ती किया जाना है, इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र **दिनांक 13.05.2025 शाम 6:00 बजे तक** आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 13.05.2025 सायं 6:00 तक** अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की वेबसाइट **www.datiamedicalcollege.com** पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, म.प्र. में जमा कराये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में **"आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी"** हेतु आवेदन और आरक्षित श्रेणी ..... का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र में से पात्र अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
जी-23015/50592/2025 **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म. प्र.)**

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, सह सचिव मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

परामर्शी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

भारत सरकार, जनजातीय कार्य, मंत्रालय अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित विशिष्ट आवासीय विद्यालय (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय) के सम्पूर्ण वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन, नवीन प्रक्रिया एवं अन्य वित्तीय कार्य हेतु संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार योजनाओं हेतु डाटाबेस निर्माण तथा योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि की मॉनीटरिंग हेतु तथा विश्लेषणात्मक बिन्दुओं/सुझावों पर प्रतिवेदन हेतु वित्तीय प्रबंधन पर परामर्शी नियुक्त करने की आवश्यकता है।

विभागीय वेबसाइट **tribal.mp.gov.in** से इच्छुक उम्मीदवार पात्रता निर्धारण की शर्तें एवं भरे जाने वाले आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। सम्पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को दिनांक 28 फरवरी 2025 अपरान्ह 5:00 बजे तक कार्यालय, आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल में व्यक्तिगत रूप से जमा किए जा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत गठित समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त, जनजातीय कार्य सह सचिव मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस), भोपाल उक्तानुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों को बिना कारण स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

आयुक्त, जनजातीय कार्य, सह सचिव
मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल
जी-23042/50596/2025 **एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS), भोपाल**

कार्यालय मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : cepwdcapital@mp.nic.in, दूरभाष/फैक्स क्रमांक : 0755-2551403

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 02/सा/01/विविध/ 2019 (वर्ष 2025) **भोपाल, दिनांक 28.01.2025**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1.	2025_ PWDRB_ 398828_1	भोपाल (राजधानी स. क्र.-2 भोपाल)	रेनोवेशन	अेरा हिल्स भोपाल स्थित वल्लभ भवन ब्लॉक-1 का रेनोवेशन एवं उन्नयन कार्य विद्युतीकरण, फायर फाईटिंग, एच.व्ही.ए.सी., एम.ई.पी., आंतरिक फर्नीशिंग एवं फर्नीचर, फसाड उन्नयन, एल.व्ही. एवं अलाइड कार्यों सहित	प्रथम	8608.00	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किये जाना है।
				योग		**8608.00**	

उपरोक्त वेबसाइट आनॅलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 21.02.2025 (17.30 बजे निर्धारित है।** विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग
जी-23036/50595/2025 **भोपाल परिक्षेत्र भोपाल**

छात्रावासों में सुनिश्चित कराएं बेहतर प्रबंध - मुख्यमंत्री

भोपाल, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास में किसी भी तरह की असुविधा न होने पाये। सभी छात्रावासों में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बच्चों को पढ़ने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाये। छात्रावास में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करें, ऐसा समय प्रबंधन किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सभी कल्याण योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, जिससे समाज के वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ मिल सके। डॉ. यादव ने कहा कि 24 जनवरी को महेश्वर में हुई कैबिनेट में महू स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में विधि संकाय प्रारंभ करने के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गये हैं। विधि संकाय प्रारंभ करने के लिए सभी तैयारियां समय रहते कर ली जायें। प्रमुख सचिव ने बताया कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू (इंदौर) को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ 40 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। प्रमुख सचिव अजा कल्याण डॉ. कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रावासों का संचालन, छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन, शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं, अनुदान कार्यक्रम और स्वरोज़गार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

कार्यालय मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : cepwdcapital@mp.nic.in, दूरभाष/फैक्स क्रमांक : 0755-2551403

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 03/सा/01/विविध/2019 (वर्ष 2025) **भोपाल, दिनांक 11.02.2025**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1.	2025_ PWDRB _401505_1	भोपाल (संधारण स. कं-2 भोपाल) मार्ग द्वारा उन्नयन	मार्ग	मिसरोद से अमझरा (चैनियाखेडी) मार्ग लं. 11.500 कि.मी. का मजबूतीकरण	प्रथम	985.26	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किये जाना है।
2.	2025_ PWDRB _401506_1	भोपाल (संधारण स.क्र.-2 भोपाल) मार्ग	मार्ग	भारत नगर कैनाल रोड लंबाई 2.60 कि.मी. का व्हाइट टॉपिंग द्वारा उन्नयन	प्रथम	617.92	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किये जाना है।
3.	2025_ PWDRB _401507_1	भोपाल (संधारण स. कं - 2 भोपाल)	मार्ग	डी.आई.जी. बंगला से कालीपरेड मार्ग लं. 2.20 कि.मी. पर व्हाइट टॉपिंग	प्रथम	582.31	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किये जाना है।
4.	2025_ PWDRB_ 401820_1	भोपाल (नया भोपाल संभाग भोपाल)	मार्ग	लो.नि.वि. नया भोपाल संभाग भोपाल के अधिनस्थ उपसंभाग क्र.-3 हबीबगंज थाना से एन.एच. 12 एवं अेरा कॉलोनी ई-5 के आंतरिक मार्ग लंबाई 3.40 कि.मी. पर व्हाइट टॉपिंग	प्रथम	1127.00	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किये जाना है।
				योग		**3312.49**	

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 28.02.2025 (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग
जी-23021/50594/2025 **भोपाल परिक्षेत्र भोपाल**

कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर

शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर (म.प्र.)-470001
Website : bmcsagar.edu.in, E-mail : deansmc08@yahoo.co.in
फोन नं. : 07582-236270, फैक्स नं. : 07582-236457

क्रमांक 1273 /क्रय/25 **सागर, दिनांक : 06.02.2025**

बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में लगने वाले कम्प्यूटर सिस्टम एवं मल्टी फंक्शन प्रिंटर के क्रय हेतु GeM पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रण-सूचना
BID NO. : GEM/2025/B/5916628

निविदा का नाम	निविदा प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में लगने वाले कम्प्यूटर सिस्टम एवं मल्टी फंक्शन प्रिंटर के क्रय हेतु निविदा	12.02.2025 दोपहर 12:00 बजे से	04.03.2025 दोपहर 12:00 बजे तक	04.03.2025 दोपहर 12:00 बजे पश्चात

इच्छुक फर्म/संस्था ऑनलाइन वेबसाइट **http/mptender.gov.in** से एवं हमारी वेबसाइट **www.bmcsagar.edu.in** से भी निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निविदा में किये गए किसी भी संशोधन की जानकारी केवल महाविद्यालय की वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई जावेगी।

अधिष्ठाता
जी-23019/50593/2025 **बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर**

मुख्यमंत्री ने कला मनीषियों को प्रदान किए राज्य शिखर सम्मान

भोपाल, कलाएं स्वयं बोलती हैं, यह हमारे व्यवहार और भावनाओं से भी व्यक्त होती हैं। मध्यप्रदेश कला की धरती है। यहां से कई विश्व मान्य कला मनीषी हुए हैं। कलाओं और कलासाधकों से ही हमारी संस्कृति पोषित है, पल्लवित है। मध्यप्रदेश को विश्व में कला गौरव स्थल की पहचान दिलाने में भारत भवन की प्रमुख भूमिका है। हम सब भारत भवन के एक गौरवशाली अतीत के गवाह हैं। आज भारत भवन की 43वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम बेहद गौरवान्वित हैं। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत भवन के मुक्ताकाश मंच से राज्य शिखर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान देते हुए वर्ष 2022 एवं 2023 के राज्य शिखर सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर 15 कला मनीषियों को उनके अतिविशिष्ट योगदान के लिए शॉल, श्रीफल, सम्मान पट्टिका एवं दो लाख रुपये की सम्मान राशि देकर अलंकृत किया गया। समारोह में संगीत, नृत्य, नाटक, जनजातीय एवं लोक कला, साहित्य तथा रंगकर्म के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों, साहित्यकारों एवं रंगकर्मियों को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया।

डॉ. यादव ने राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित सभी कला विभूतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। कलाकार हमारे समाज की आत्मा हैं और उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने भारत भवन के 43वें स्थापना दिवस को खास बनाते हुए यहां रंगमण्डल को पुनः प्रारंभ करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगमण्डल की वापसी सिर्फ रंगमंच ही नहीं, बल्कि पूरे कला जगत के लिए एक नया आनंद लेकर आयेगी।

संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश
गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स, टी.टी. नगर न्यू मार्केट भोपाल-462003

विज्ञप्ति

क्रमांक : 202/स्था/संसैक/2025/316 **दिनांक : 06 फरवरी, 2025**

1. संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु केवल भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित हैं :-

क्रमांक	पद	संख्या	आरक्षण
1.	अधीक्षक	01	अनारक्षित
2.	कल्याण संयोजक	03	अनारक्षित-02 एवं अनुसूचित जनजाति-01

2. आवेदन का प्रारूप, अर्हता एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट **https://sainikkalyan.mp.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।
3. भूतपूर्व सैनिक अपना आवेदन जिस जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत है, से डाक के माध्यम से **दिनांक 25 फरवरी 2025 तक** भेजना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

जी-22810/50575/2025 **संचालक**

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग
निर्माण भवन, प्लाट नं.- 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं. - 03/2025/निविदा/सा/मु.अ.भ./ **भोपाल, दिनांक : 30.01.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 सीटेड के.जी. वी.बी. टाइप-III होस्टल बिल्डिंग राज्य शिक्षा केंद्र एट कामती रंगपुर डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम (द्वितीय आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2025_PWPIU_400148_1	नर्मदापुरम	145.40	145400	12500	10 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 30.01.2025 समय 10.30 से **दिनांक 17.02.2025** समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (भवन)
जी-22771/50576/2025 **लोक निर्माण विभाग भोपाल**

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ce.tender.wrdmp@gmail.com, फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1128/2024-25/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 05.02.2025**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 04.03.2025** को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2025_WRD_399525	हनौता सिंचाई परियोजना से प्रभावित पुनर्वासन स्थल ग्राम गौदखेड़ी के समर्पित फिडर हेतु स्थापित 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र पठारी पर 5 एम.व्ही.ए. पी.टी.आर. सहित व्ही.सी.बी. के प्रदाय सहित स्थापना का कार्य समस्त सामग्री एवं मजदूरी सहित।	सागर	153.24
2.	2025_WRD_399526	रामपुरा की बेसला तालाब योजना की नहरों का लाइनिंग कार्य। (विशेष मरम्मत)	नीमच	35.36
3.	2025_WRD_399527	मोहनपुरा परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली अंतर्गत पीपलबे पम्प हाउस में मौजूदा एच.टी. 11 के.वी. फीडर का 33 के.वी. फीडर से इंटरकनेक्शन का कार्य।	राजगढ़	92.81
4.	2025_WRD_399528	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से कटिला-पचा वृहद सिंचाई परियोजना की पर्यावरण मंजूरी का कार्य।	शिवपुरी	245.24
5.	2025_WRD_399530	हसलपुर तालाब का विशेष मरम्मत कार्य।	इंदौर	103.31

जी-22790/50573/2025 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ce.tender.wrdmp@gmail.com, फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1129/2024-25/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 05.02.2025**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 04.03.2025** को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2025_WRD_400930	मोहनपुरा परियोजना के बाएं तट लिफ्ट प्रणाली के नवीनीकरण का कार्य।	राजगढ़	1114.69

मुख्य अभियंता
जी-22794/50574/2025 **(प्रोक्योरमेंट)**

राज्यपाल का सचिवालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)
(प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना हेतु विज्ञप्ति)

क्रमांक : 306A/रास/स्था/2025 **भोपाल, दिनांक : 4 फरवरी, 2025**

राज्यपाल सचिवालय, भोपाल में रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर किये जाने हेतु राज्यशासन के विभिन्न विभागों तथा राज्य शासन के निगम, मंडल, उपक्रम, में समकक्ष पद व वेतनमान पर कार्यरत एवं इच्छुक शासकीय, अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

तत्संबंध में आवश्यक जानकारी राजभवन की वेबसाइट **http://governor.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। केवल पात्र व्यक्ति ही आवेदन करें। आवेदन की **अंतिम तारीख 10.03.2025** है। यदि विज्ञप्ति में कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी सूचना राजभवन की विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।

राज्यपाल के अपर सचिव
जी-22874/50577/2025 **मध्यप्रदेश भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग टीकमगढ़, म.प्र.

Phone No. : 07683-242321, Email : eepwdtikam@mp.nic.in

एनआईटी नं. 11/2024-25/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण **दिनांक : 10.02.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

क्र. एवं कार्य का नाम - 1. चौबारा से देवपुर मार्ग लं. 2.00 कि.मी. एवं बन्ने बुजुर्ग से बन्ने खुर्द लं. 3.00 कि.मी. का निर्माण कार्य मय विद्युतीकरण सहित।

पोर्टल टेंडर क्र.	निविदा आमंत्रण क्रमांक	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पी.ए.सी.) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2025_PWDRB_401462_1	प्रथम	टीकमगढ़	376.61	376610.00	15000.00	06 माह वर्षाकाल सहित

क्र. एवं कार्य का नाम - 2. चंद्रपुरा से खरगापुर रेलवे स्टेशन मार्ग निर्माण लं. 5.00 कि.मी. मय विद्युतीकरण सहित।

2025_PWDRB_401464_1	प्रथम	टीकमगढ़	413.20	413200.00	15000.00	08 माह वर्षाकाल सहित
		कुल राशि	**789.81**	**789810.00**	**30000.00**	

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 12.02.2025 से **दिनांक 27.02.2025** समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-22951/50578/2025 **लोक निर्माण विभाग, संभाग टीकमगढ़**

आईटी और प्रौद्योगिकी में अग्रणी मध्यप्रदेश करेगा भारत के डिजिटल भविष्य का निर्माण

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आईटी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से नई ऊर्जा मिलेगी। इस सेक्टर के लिए समिट में अलग से सत्र आयोजित होगा। मध्यप्रदेश में 15 से अधिक आईटी पार्क और 5 आईटी एसईजेड हैं, जिनमें इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क और इंफोसिस जैसे प्रमुख सेंटर शामिल हैं। ये पार्क विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हैं, जो टीसीएस, इंफोसिस और एक्सेंचर जैसी प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करते हैं। नॉलेज सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 जैसी आगामी परियोजनाएं, इस इको सिस्टम को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं।

परिवर्तन के दौर से गुजर रहे देश के तकनीकी इको सिस्टम के विकास के अगले केन्द्र टीयर-2 शहर हैं, जो टेक इनोवेशन और निवेश के नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इसकी वजह है यहां कम परिचालन लागत, उच्च जीवन स्तर और कुशल प्रतिभा पूल की उपलब्धता। टीयर-2 शहर अब तकनीकी कंपनियों की पसंद बनते जा रहे हैं। खास बात है कि मध्यप्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलेंट और लागत-दक्षता प्रदान करने वाला अग्रणी राज्य है।

मध्यप्रदेश का व्यापक आईटी, आईटीईएस और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विश्वस्तरीय आईटी पार्क, नॉलेज और सॉफ्टवेयर हब के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने से निश्चित रूप से मध्यप्रदेश तकनीकी क्रांति की अगली लहर का नेतृत्व करेगा।

300 से अधिक तकनीकी शिक्षा संस्थान

मध्यप्रदेश की विशेषता है कि 300 से अधिक तकनीकी शिक्षा संस्थान सालाना 50 हजार से अधिक तकनीकी स्नातक तैयार करते हैं। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर और आईआईआईटी ग्वालियर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अत्यधिक कुशल युवाओं को गढ़ते हैं। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क उद्योग के लिए कौशल संपन्न पेशेवर तैयार करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की प्रगतिशील नीतियां और इनोवेशन को बढ़ावा देने और तकनीक के क्षेत्र में विश्वस्तरीय दिग्गज कंपनियों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। मध्यप्रदेश का मजबूत पॉलिसी-स्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी संचालित विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025, एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी 2025, ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 और सेमीकंडक्टर नीति 2025 शामिल हैं।

टेलेंट और इनोवेशन को बढ़ावा

प्रदेश सरकार के फोकस में उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ टेलेंट और इनोवेशन को बढ़ाते हुए आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर हब और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण निवेश हैं। अग्रणी तकनीकी हब बनने की दृष्टि के साथ मध्यप्रदेश डिजिटल भविष्य को शक्ति प्रदान करने के रास्ते पर अग्रसर है। आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है, जो कैपेक्स, भूमि, ब्याज छूट, मार्केटिंग और पेटेंट सहायता आदि प्रदान करती है। दूसरी ओर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025 वैश्विक तकनीकी केंद्रों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कैपेक्स, पेरोल और अपस्किलिंग के लिए सब्सिडी, आरएंडडी को सपोर्ट करती है।

इसी तरह एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी-2025 एवीजीसी सेक्टर को सपोर्ट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, उत्पादन संबंधी वित्तीय सहायता, उद्योग सहयोग और एवीजीसी-एक्सआर लैब की स्थापना आदि के लिए सहयोगी है।

योजना

प्रदेश के युवाओं के सपनों को पंख लगाती मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए 10 जनवरी, 2022 से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गयी। इस योजना में अब तक 67500 लाभार्थी हैं तथा 3 हजार 772 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा समग्र रूप से प्रयास किया जा रहा है। योजना से मिलने वाले लाभ का परिणाम है कि अब प्रदेश के युवा नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए क्यू आर कोड स्कैन कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, खुदरा व्यवसाय आदि स्थापित करने के लिये बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध करवाना है।

परियोजना सीमा

मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में - इस योजना के तहत 50 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

सेवा क्षेत्र में - 50 हजार रुपये से 25 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

खुदरा व्यापार के लिए - 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकतम परियोजना सीमा से अधिक राशि की परियोजनाएं स्वीकार की जा सकती हैं, परंतु ऐसे प्रकरणों में हितग्राही को योजनांतर्गत वित्तीय सहायता, ब्याज अनुदान तथा ऋण राशि 50 लाख अथवा ऋण राशि रुपये 25 लाख रुपये (सेवा/खुदरा व्यवसाय इकाई) तक ही यथानुपात आधार पर प्राप्त होगा।

योजना से लाभ

योजना अंतर्गत बैंक-ऋण पर

- ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(त्रैमासिक आधार पर देय)

- ऋण गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति।
- कोलेटरल की आवश्यकता नहीं।
- यह लाभ-अधिकतम 7 वर्षों के लिये है।

योजना के लिए पात्रता

- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो।
- शिक्षा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
- लाभार्थी की आयु 18-45 वर्ष।
- **पारिवारिक आय-** 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

- वर्तमान में किसी अन्य सरकारी स्वरोज़गार योजना का लाभार्थी न हो।

नवीन इकाई हेतु आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक पात्र अथवा आवेदक स्वयं या एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से https://samast.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- नवीन फोटो।
- आवेदक के हस्ताक्षर।
- आवेदक का आधार कार्ड एवं पेन कार्ड।
- शैक्षणिक योगयता का प्रमाण-पत्र। (न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट)।
- जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- कोटेशन।
- मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

(निर्धारित प्रपत्र पर स्व-प्रमाणित प्रति भी मान्य)

- किरायानामा (यदि भवन किराए का हो)
- आयकर दस्तावेज (ITR) पिछले 3 वर्षों के (यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है तो)
- अन्य दस्तावेज (यदि लागू हों तो)

आवेदन करते समय आवेदक को यह बताना होगा कि उसे कितना ऋण चाहिए एवं किस बैंक के माध्यम से चाहिए।

व्यवसाय के क्षेत्र

ट्रेडिंग (व्यवसायिक) गतिविधियां:- किराना स्टोर, स्टेशनरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक शॉप, गारमेंटशॉप, ऑटो पार्ट्स, टॉय शॉप, स्पोर्टस प्रोडक्ट शॉप, वेजिटेबल शॉप इत्यादि

सर्विस क्षेत्र- रेस्टोरेंट, एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, ऑटो-मोबाइल रिपेयरिंग, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, कंसल्टेंसी और परिवहन सेवा इत्यादि।

मैन्यूफैक्चरिंग - फूड प्रोडक्ट, मेटल प्रोडक्ट, स्टील प्रोडक्ट, पेपर प्रोडक्ट, सीमेंट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आर.ओ. वॉटर प्लांट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पी.वी.सी. पाईप निर्माण और नॉन वोवन इत्यादि का निर्माण।

योजना का क्रियान्वनय - एमएसएमई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

संपर्क - अधिक जानकारी के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संपर्क कर सकते हैं।

पोर्टल (http://samast.mponlne.gov.in)

- हितेश शर्मा

(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

केंद्रीय बजट 2025-26

ग्रामीण समृद्धि, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन से आत्मनिर्भर होगा भारत

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में खेती, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कर व्यवस्था और उद्यमिता के क्षेत्र में नई योजनाओं और पहलों की घोषणा की गई है। इन पहलों के माध्यम से न केवल ग्रामीण भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा, बल्कि इससे पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक संतुलन भी बढ़ेगा। बजट में सरकार ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां विकास की गति धीमी रही है, ताकि इन क्षेत्रों को समान अवसर मिल सकें और समग्र विकास संभव हो सके। इस लेख में हम उन योजनाओं और पहलों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनकी घोषणा इस बजट में की गई है, और जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

भारत की अधिकांश आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों की खुशहाली से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना, किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना विशेष रूप से उन जिलों के किसानों के लिए शुरू की जाएगी, जहां कृषि उत्पादकता कम है और ऋण प्राप्ति के मानदंड भी औसत से कम हैं। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को चिह्नित किया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एक समावेशी और विकासशील कृषि कार्यक्रम होगा, जिसे राज्यों की भागीदारी से लागू किया जाएगा।

मध्यम वर्ग के लिए कर सुधार

केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कई सकारात्मक और दूरदर्शी कदम उठाए हैं, जिनसे न केवल उनकी कर देनदारी में कमी आएगी, बल्कि उन्हें नए अवसरों का भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझते हुए एक ऐसी कर व्यवस्था प्रस्तावित की है, जो मध्यम वर्गीय करदाताओं के लिए राहत देने वाली साबित होगी। नई कर संरचना के अनुसार, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी व्यक्ति की औसत मासिक आय 1 लाख रुपये तक है, तो वह आयकर से मुक्त होगा। इसके अलावा, यदि वेतनभोगी करदाता हैं, तो वे 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कर से मुक्त हो जाएंगे। यह एक बड़ा सुधार है, क्योंकि इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि इससे उनकी उपभोग शक्ति भी बढ़ेगी, जो देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करेगी।

जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर

कैंसर आज के समय में एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। यह लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। इस बीमारी के इलाज के दौरान मरीजों को कई प्रकार की दवाइयों और चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में कैंसर के इलाज की सुविधा का अभाव होता है, जिससे लोगों को इलाज के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन डे-केयर कैंसर केंद्रों में मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी। मरीज दिन के समय इलाज लेकर शाम को घर लौट सकते हैं। यह केंद्र मरीजों के समय और पैसों की बचत करने के साथ-साथ इलाज की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेंगे। सरकार ने अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2025-26 में 200 कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह योजना न केवल कैंसर के इलाज की प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी बढ़ाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कैंसर के इलाज को सुलभ और किफायती बनाना है। गांव और छोटे शहरों के ऐसे लोग, जो आमतौर पर महंगे इलाज के कारण उपचार से वंचित रहते हैं, उन्हें यह केंद्र सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह क्षेत्र न केवल रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। हालांकि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को अक्सर पूंजी और वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो उनकी वृद्धि और विकास में रुकावट डालता है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण साबित होंगे। इस कार्ड के माध्यम से सूक्ष्म उद्योग अपना कारोबार चलाने के लिए आवश्यक सामग्री, उपकरण या सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा यह कार्ड सूक्ष्म उद्यमियों को अपने नकदी प्रवाह को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की सुविधा भी देगा, जिससे उनका कारोबार सुचारु रूप से चल सके। इस पहल से छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों को न केवल अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि यह उन्हें रोज़गार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छोटे व्यवसायी अपने व्यापार के लिए पूंजी जुटा सकेंगे। यह उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और अंततः अधिक रोज़गार सृजन होगा।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों में लगे हुए हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आमतौर पर वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर ऋण प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि इनकी कोई मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। इस समस्या को हल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। यह ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। क्रेडिट स्कोर एक मानक होता है, जिसका उपयोग करके वित्तीय संस्थाएं और बैंक किसी व्यक्ति की लोन लेने की क्षमता का मूल्यांकन करती हैं। यह स्कोर बैंक को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है या नहीं। शहरों में यह स्कोर आमतौर पर व्यक्ति के लोन और अन्य वित्तीय लेन-देन के आधार पर तैयार होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अधिकांश लोग इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करते, वहां एक सामान्य क्रेडिट स्कोर सिस्टम काम नहीं करता। 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' फ्रेमवर्क का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के लिए एक ऐसा स्कोर तैयार करना है, जो उनकी वित्तीय क्षमता और ऋण लेने की संभावना का आकलन कर सके।

बजट में 'सबका विकास' को प्राथमिकता

इसके अलावा बजट में देश के समग्र और संतुलित विकास के लिए कई अहम पहलुओं को रेखांकित किया गया है। बजट में 'सबका विकास' के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही इसके माध्यम से समस्त क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारत के समग्र विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बताई। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए कई क्षेत्रीय और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत भी बताए, जो हैं -

- गरीबी से मुक्ति।
- शत-प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा।
- बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच।
- शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोज़गार।
- आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं।
- हमारे देश को 'फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड' बनाने वाले किसान।

- निशा त्यागी

(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं और सम-सामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं)

जॉब अलर्ट

सीमा सड़क संगठन

पद का नाम - बहु कुशल कर्मकार (रसोईया, राजमिस्त्री, लोहार, भोजनशाला बैरा)
पदों की संख्या - 411
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 24 फरवरी, 2025
वेब. - https://marvels.bro.gov.in

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क का आयुक्त कार्यालय

पद का नाम - सीमैन, ग्रीसर, ट्रेड्समैन, टिंडल, इंजन ड्राइवर
पदों की संख्या - 14
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 20 फरवरी, 2025
वेब. - https://www.cbic.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड

पद का नाम - 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवन के तहत विभिन्न पद
पदों की संख्या - 32438
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 22 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://rrbahmedabad.gov.in

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

पद का नाम - आशुलिपिक ग्रेड-III
पदों की संख्या - 144
योग्यता - मान्यता प्राप्त बोर्ड से कला, विज्ञान या वाणिज्य विषय के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा कम्प्यूटर प्रचालन का डिप्लोमा एवं अन्य वांछित योग्यताएं।
अंतिम तिथि - 23 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://hcraj.nic.in

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

पद का नाम - चार्जमैन (इलेक्ट्रिकल), इलेक्ट्रिशियन 'ए', इलेक्ट्रिशियन 'बी', वेड 'बी'
पदों की संख्या - 103
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 25 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://www.hindustan-copper.com

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

पद का नाम - प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर
पदों की संख्या - 14
योग्यता - संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी उपाधि
अंतिम तिथि - 23 फरवरी, 2025
वेबसाइट - http://www.niperhyd.ac.in

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पद का नाम - जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट
पदों की संख्या - 246
योग्यता - जूनियर ऑपरेटर के लिए मैट्रिक के साथ संबंधित विषय में आईटीआई उत्तीर्ण, जूनियर अटेंडेंट के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि।
अंतिम तिथि - 23 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://iocl.com

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

पद का नाम - उप प्रबंधक (तकनीकी)
पदों की संख्या - 60
योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर की डिग्री
अंतिम तिथि - 24 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://nhai.gov.in

आयुध निर्माणी, इटारसी

पद का नाम - कार्यकाल आधारित सीपीडब्ल्यू, स्नातक अप्रेंटिस
पदों की संख्या - 127
योग्यता - कार्यकाल आधारित सीपीडब्ल्यू के लिए आयुध निर्माणी या अन्य शासकीय संबद्ध संस्थानों/संगठनों से ओसीपी ट्रेड के पूर्व प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) तथा स्नातक अप्रेंटिस के लिए स्नातक डिग्री।
अंतिम तिथि - 20 फरवरी, 2025
वेब. - https://munitionsindia.in

भारतीय तटरक्षक बल

पद का नाम - नाविक (सामान्य ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा)
पदों की संख्या - 116
योग्यता - नाविक (सामान्य ड्यूटी) के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिकी विषय के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा नाविक (घरेलू शाखा) के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यका
अंतिम तिथि - 25 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://joinindiancoastguard.cdac.in

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर

पद का नाम - सीनियर रेजीडेंट
पदों की संख्या - 100
योग्यता - आवेदक के पास चिकित्सा शिक्षा की स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है।
अंतिम तिथि - 23 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://aiimsbhubaneswar.nic.in

भारतीय नौसेना

पद का नाम - लघु सेवा आयोग अधिकारियों की भर्ती (सब लेफ्टिनेंट)
पदों की संख्या - 270
योग्यता - न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि
अंतिम तिथि - 25 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://www.joinindianavy.gov.in

एडमिशन अलर्ट

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला

पाठ्यक्रम का नाम - सटीक मापन और गुणवत्ता नियंत्रण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
सीटों की संख्या- 25
योग्यता- बी.एससी. (भौतिकी और गणित) / बी.एससी. इंजीनियरिंग / बीई/ बी.टेक. (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / इंस्ट्रूमेंटेशन)
अंतिम तिथि - 28 फरवरी, 2025
वेबसाइट - https://www.nplindia.org

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

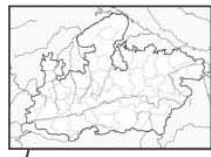

हमारा जिला छिंदवाड़ा

जनजातीय कला, संस्कृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समृद्ध है छिंदवाड़ा

मध्यप्रदेश विविधता से समृद्ध है। प्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है। यहां का प्रत्येक जिला अपना इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, उपज और अन्य क्षेत्रीय विशेषताएं लिए हुए है। 'रोज़गार और निर्माण' के 'हमारा जिला' स्तम्भ में हम मध्यप्रदेश के जिले से आपको परिचित करवाते हैं। इस अंक में प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले का परिचय-

छिंदवाड़ा जिला सतपुड़ा रेंज के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह जिला दक्षिण में नागपुर जिले के मैदानों, उत्तर में नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिले, पश्चिम में बैतूल जिला और पूर्व में सिवनी जिले की सीमाओं से लगा हुआ है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल जनसंख्या 15,68,702 है। अनुसूचित जाति की आबादी 1,91,419 है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5,40,708 है।

एक जिला एक उत्पाद - संतरा

जिले में संतरे का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है। यहां का संतरा पतले छिलके वाला रसभरा है। एक जिला एक उत्पाद के तहत यहां का संतरा अब देशभर में सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है।

भौगोलिक संरचना

भौगोलिक दृष्टि से छिंदवाड़ा जिले को तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला नागपुर क्षेत्र के पास के इलाकों में तहसील सौंसर और पांढुर्ना शामिल हैं, दूसरा मध्य क्षेत्र में छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा के दक्षिणी भाग और सौंसर के उत्तरी भाग क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है और तीसरा ज्यादातर उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ी इलाके का है। यहां पांच प्रमुख नदियां हैं, जिनके नाम हैं कान्हा, पेंच, जाम, कुलबेहरा, शक्कर और दूधा।

संस्कृति

छिंदवाड़ा जिला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। जनजाति समुदायों में मुख्य रूप से गोंड, परधान, भारिया, कोरकू आदि शामिल हैं। जिले में हिंदी, मराठी, गोंडी, उर्दू, कोरकू, मुसाई और पारवारी आदि भाषाओं तथा बोलियों का उपयोग होता है। पांढुर्ना का गोतमभ मेला अद्वितीय और प्रसिद्ध है। चौरागढ़ में महाशिवरात्रि को महादेव मेले का आयोजन होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बुलंद राजा के शासन के समय से यहां का राज्य सतपुड़ा सीमा तक विस्तारित था। माना जाता है कि उनका शासन तीसरी शताब्दी तक था। एक प्राचीन पट्टिका, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, जो नीलकंठ गांव में पायी गयी है। इस राजवंश ने 7वीं सदी तक शासन किया फिर गोंडवाना वंश आया। गोंड राजा जाटव ने देवगढ़ किले का निर्माण किया। बाद में कई शासकों ने यहां राज्य किया, मराठा शासन 1803 में समाप्त हो गया। 17 सितंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया। 1 नवंबर 1956 को यह मध्यप्रदेश का जिला बन गया।

पेंच राष्ट्रीय उद्यान - जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा पहाड़ियों के निचले दक्षिणी इलाकों में स्थित है। इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। यह सीओनी और छिंदवाड़ा जिलों में महाराष्ट्र के किनारे मध्यप्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। पेंच नेशनल पार्क का क्षेत्र 758 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से 299 वर्ग किलोमीटर इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र और मोगली पेंच अभयारण्य और शेष 464 वर्ग किलोमीटर पेंच राष्ट्रीय उद्यान बफर क्षेत्र है।

तामिया - मध्यप्रदेश में तामिया एक सुरम्य वन क्षेत्र है। यहां घने जंगल और पहाड़ हैं। पूर्ण शांति का अनुभव करने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। पहाड़ी की चोटी पर कुछ घर बने हैं। यह पहाड़ियों, विशाल हरियाली और गहरे घाटियों का मनोरम स्थल है। तामिया किसी भी प्रकार के व्यावसायीकरण से दूर है।

मुख्य स्थल

हिंगलाज माता मंदिर - हिंगलाज माता मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भारत में केवल दो हिंगलाज मंदिर हैं, एक पाकिस्तान की सीमा के पास है और दूसरा छिंदवाड़ा जिले के पास अंबारा में है। यह दक्षिण में स्थित (परसिया रोड द्वारा), शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है।

हनुमान मंदिर जाम सांवली - श्री हनुमान मंदिर जाम सांवली मध्यप्रदेश के प्राचीन क्षेत्र में दंडकारण्य-सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। जो जाम नदी और सांवली गांव में सरपा नदी के संगम पर स्थित है। नागपुर से 66 किलोमीटर की दूरी पर, नागपुर-छिंदवाड़ा रोड पर बजाज जोंइटचोक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि यहां श्री हनुमान स्वयं प्रकट हुए।

कुपुर्दा माता मंदिर - चौरई में स्थित यह मंदिर षष्ठी माता मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान षष्ठी माता की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मान्यता है कि षष्ठी माता का आशीर्वाद उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जिन्हें शादी के कई साल बाद भी संतान नहीं होती है।

हनुमान मंदिर सिमरिया - जिले के सिमरिया गांव में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में

भगवान हनुमान की 101 फीट ऊंची मूर्ति है। यह मंदिर परिसर पांच एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह वह बिंदु है जहां कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य से आता है और मध्यप्रदेश में प्रवेश करता है। मंदिर परिसर इस तरह से स्थित है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान हनुमानजी की मूर्ति भक्तों को आशीर्वाद दे रही है।

पातालकोट छिन्दवाड़ा - छिंदवाड़ा जिले के पहाड़ी ब्लॉक तामिया में पातालकोट स्थित है। पातालकोट एक सुंदर

पर्यटन स्थल है, जो एक घाटी में 1200-1500 फीट की गहराई पर स्थित है। जिस स्थान पर यह स्थित है, उसकी गहराई के कारण इसे 'पातालकोट' के नाम से जाना जाता है। जब कोई घाटी के शीर्ष पर बैठे हुए इस स्थान को देखता है, तो वह आकार में घोड़े के पैर जैसा दिखता है। लोग इसे पातालकोट के प्रवेश द्वार के रूप में मानते हैं। एक और मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद मेघनाथ केवल इसी स्थान से पाताल-लोक गए थे। यह स्थान उत्तर-पश्चिम दिशा में जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर और उत्तर-पूर्व दिशा में तामिया से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पातालकोट 79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां दूध नदी सुरम्य घाटी में बहती है। यहां वन और हर्बल संपदा की विपुलता है। इस घाटी में 12 गांव और 13 बस्तियां हैं। अधिकांश लोग 'भारिया' और 'गोंड' जनजाति के हैं। इस क्षेत्र की दुर्गमता के कारण, पूर्व में यह जनजातियां शहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गई थीं। लेकिन, सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के चलते इस क्षेत्र में अब बदलाव आया है।

ट्राइबल म्यूजियम - 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में शुरू किए गए ट्राइबल म्यूजियम ने वर्ष 1975 में स्टेट म्यूजियम का स्थान प्राप्त किया और 8 सितंबर 1997 को ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम किया गया है। श्री बादल भोई जिले के एक क्रांतिकारी जनजाति नायक थे। उनके नेतृत्व में 1923 में हजारों लोगों ने कलेक्टर बंगला में प्रदर्शन किया था। लाठीचार्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अगस्त 1930 को उन्हें अंग्रेजी शासक द्वारा रामाकोना पर वन नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 1940 में अंग्रेजी शासक द्वारा उन्हें जहर दिया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण, जनजातीय संग्रहालय का नाम बदलकर 'श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय' किया गया है। 15 अगस्त 2003 से, आदिवासी संग्रहालय पर्यटकों के लिए रविवार को भी खोला जाता है। संग्रहालय में 14 कमरे, 3 गैलरी और दो खुली गैलरी शामिल हैं। इसमें जनजातीय संस्कृति को दर्शाया गया है। यह मध्यप्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जनजातीय संग्रहालय है।

गोटमार मेला - छिंदवाड़ा से पैंसठ किलोमीटर दूर, पांढुर्णा के मुख्यालय में एक अनूठा गोटमार मेला हर साल भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह मेला 'जाम' नदी के तट पर मनाया जाता है।

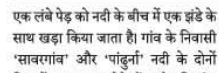

एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। गांव के निवासी 'सावरगांव' और 'पांढुर्ना' नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं, और विपरीत गाँव के व्यक्तियों पर पथराव शुरू करते हैं, और नदी के बीच में जाकर झंडा हटाने की कोशिश करते हैं। जिस गांव का निवासी झंडा हटाने में सफल होता है, उसे विजयी माना जाता है। पूरी गतिविधि मां दुर्गाजी के जप के साथ होती हैं।

- देवेन्द्र गोरे
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

खेल चर्चा

नई स्कोरिंग प्रणाली का परीक्षण करेगा बीडब्ल्यूएफ

क्वालालंपुर, खेल के प्रति नए दर्शकों को आर्कषित करने तथा मैचों को छोटा करने के उद्देश्य से बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) नई स्कोरिंग प्रणाली का परीक्षण करेगा। यह स्कोरिंग प्रणाली इस वर्ष अप्रैल से कम से कम छह माह के लिए चुनिंदा प्रतियोगिताओं में लागू की जाएगी। बीडब्ल्यूएफ परिषद ने क्वालालंपुर में आयोजित बैठक के दौरान 15 अंक के तीन गेम वाली स्कोरिंग प्रणाली का समर्थन किया। मौजूदा समय में बैडमिंटन खेल में 21 अंक के बेस्ट ऑफ थ्री गेम (दो गेम जीतने वाला विजेता) वाली स्कोरिंग प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि मौजूदा प्रणाली की तुलना में 15 अंक के तीन गेम में कम अंक होते हैं, जिससे मैच का प्रत्येक अंक रोमांचक और महत्वपूर्ण बन जाता है। 15 अंक के तीन गेम वाली स्कोरिंग प्रणाली से मैच छोटे होंगे, परिणाम जल्दी निकलेगा और दर्शकों की दिलचस्पी भी बनी रहेगी।

राष्ट्रीय खेल-2025

मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों का स्वर्णिम प्रदर्शन

देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश समाचार लिखे जाने तक 28 स्वर्ण 19 रजत और 22 कांस्य सहित 69 कुल पदक जीतकर पदक तालिका में पांचवें स्थान पर काबिज है।

देव मीणा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक

राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के एथलीट देव मीणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। देव ने स्पर्धा में 5.32 मीटर की छलांग लगाकर न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, बल्कि इस स्पर्धा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले इस स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तमिलनाडु के सुब्रमणि शिवा (5.31 मीटर) के नाम था। इसके अलावा शॉटपुट व्यक्तिगत पुरुष स्पर्धा में मध्यप्रदेश के समरदीप सिंह गिल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। समरदीप सिंह ने 19.38 मीटर का थ्रो किया, वह मात्र 36 सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए।

प्रदेश के मुक्केबाजों ने जीते 5 पदक

राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के मुक्केबाजों ने अपने दमदार मुक्कों से जमकर पदक बरसाए। प्रदेश के मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, एक रजत और

तीन कांस्य सहित कुल पांच पदक जीते। प्रदेश की दिव्या पवार ने महिलाओं की बैंटमवेट (54 किलोग्राम भार वर्ग) स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष हैवीवेट (92 किलोग्राम भार वर्ग) स्पर्धा में पारस ने रजत पदक जीता। प्रदेश के हिमांशु श्रीवास ने 57 किलोग्राम वर्ग, मलिका मोर ने 50 किलोग्राम वर्ग और हनी यादव ने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते।

नीरू ढांडा ने शॉटगन में जीता स्वर्ण पदक

प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की निशानेबाज नीरू ढांडा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की शॉटगन ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। नीरू ने दिल्ली की कीर्ति और हरियाणा की आशिमा को हराया। इस स्पर्धा में कीर्ति ने रजत पदक जीता वहीं आशिमा ने कांस्य पदक हासिल किया।

मलखंब में ऐतिहासिक प्रदर्शन

मलखंब में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। मलखंब की पुरुष और महिला दोनों वर्गों की सीनियर टीमों ने टीम चैम्पियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। मलखंब की पुरुष टीम चैम्पियनशिप में देवेंद्र पाटीदार, कुंदन कछावा, यतिन कोरी और युवराज घडके की टीम ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मलखंब की एथेटस पुरुष स्पर्धा में देवेंद्र पाटीदार ने तथा एथेटस महिला स्पर्धा में सिद्धि गुप्ता ने कांस्य पदक जीते।

- **राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश ने 28 स्वर्ण पदकों के साथ जीते 69 पदक।**
- **मध्यप्रदेश की कावेरी डिमर ने महिलाओं की 500 मीटर सी-2 स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक।**
- **प्रदेश के सुनील डबर ने 5 हजार मीटर रेस में जीता कांस्य पदक।**
- **कैनोइंग स्प्रिंट 500 मीटर के-2 स्पर्धा में प्रदेश की डैली बिश्नोई ओर मनस्वानी स्वाई की जोड़ी ने जीता रजत पदक।**

कार्लोस अलकराज ने जीता रॉटरडेम ओपन

रॉटरडेम, स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने रॉटरडेम ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही अलकराज रॉटरडेम ओपन के 52 वर्ष के इतिहास में पहले स्पेनिश चैम्पियन बन गए हैं। टूर्नामेंट के फाइनल में अलकराज ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डि मिनॉर को 6-4, 3-6, 6-2 से हराया। मैच के पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया लेकिन अलकराज ने बेहतरीन सर्विस की दम पर यह सेट 6-4 से जीता। दूसरे सेट में मिनॉर ने शानदार पलटवार किया और 6-3 से जीत दर्ज की। मैच का तीसरा सेट निर्णायक रहा। इस सेट में दोनों खिलाड़ियों से कांटे के मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन अलकराज की चुनौती के सामने मिनॉर टिक नहीं सके और अलकराज ने 6-2 से सेट जीतकर खिताब अपने नाम किया।

भारत-इंग्लैंड वन-डे सीरीज

भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप की सीरीज

अहमदाबाद, युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की शानदार शतकीय पारी के दम पर भारत ने अहमदाबाद में खेले गए वन-डे मैच में इंग्लैंड को 142 रन से हराया। इस जीत की बदौलत भारत ने तीन मैचों की वन-डे सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली है। भारतीय टीम की जीत के हीरो शुभमन रहे।

मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा (1) के जल्द आउट होने के बाद शुभमन और विराट कोहली ने पारी को संभाला और 116 रन की साझेदारी की। विराट ने 52 रन बनाये, जबकि शुभमन ने 112 रनों की शतकीय पारी खेली। इनके बाद श्रेयस अय्यर (78) और के.एल. राहुल (40) ने तेजी से रन बनाये, जिसकी बदौलत भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में 356 रन बनाने में सफल रही।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम को बेन डकेट (34) और फिल सॉल्ट (23) ने मजबूत शुरुआत दिलाई, लेकिन

- **भारत ने 12वीं बार वन-डे सीरीज की क्लीन स्वीप।**
- **शुभमन ने अपने वन-डे कैरियर का सातवां शतक लगाया।**
- **शुभमन एक ही मैदान पर तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने।**
- **शुभमन वन-डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।**

इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी बिखर गई। हालांकि टॉम बेंटन और गस एटकिंसन ने 38-38 रनों की पारी खेली, लेकिन वे टीम को हार से नहीं बचा सके। इंग्लैंड की टीम 34.2 ओवरों में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

बेलिंडा बेनसिक ने जीता अबुधाबी ओपन

अबुधाबी, स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिक ने अबुधाबी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग के फाइनल में बेनसिक ने अमेरिका की एश्ल्रिन क्रूगेर को 4-6, 6-1, 6-1 से हराया। मैच के पहले सेट में क्रूगेर ने शानदार खेल दिखाया और बेनसिक को 6-4 से मात दी। दूसरे सेट में बेनसिक ने जबरदस्त पलटवार किया और क्रूगेर को एकतरफा अंदाज में 6-1 से हराया। मैच के तीसरे सेट में भी बेनसिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

ईएफएल कप के फाइनल में पहुंचा लिवरपूल

लंदन, इंग्लैंड के लोकप्रिय फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने इंग्लिश फुटबॉल लीग कप (ईएफएल) के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में लिवरपूल ने टॉटनहेम हॉटस्पर को 4-1 से हराया। सेमीफाइनल के पहले चरण में टॉटनहेम हॉटस्पर ने 1-0 से जीत दर्ज की, लेकिन दूसरे चरण में लिवरपूल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4-0 से मुकाबला जीता।

नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप

मध्यप्रदेश ने जीते एक स्वर्ण सहित छह पदक

गुलमर्ग, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गुलमर्ग में आयोजित 11वें नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक सहित कुल छह पदक अपने नाम किए हैं।

टूर्नामेंट के यूथ बालिका वर्ग में मध्यप्रदेश की अपूर्वा, अदिति, रेनु और हिमांशी ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक तथा टीम टारगेट इवेंट में रजत पदक हासिल किया। वहीं यूथ बालक वर्ग में राहिल खान, जीशान अहमद, फरदीन खान और कृष्णकांत ने टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता।

प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की रेनू, हिमांशी मांडवी, ईशिका नानकर और फलक पवार की टीम ने जूनियर बालिका टीम इवेंट में रजत पदक जीता वहीं टीम टारगेट इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इसी तरह मध्यप्रदेश के हर्षित जैन, आदेश अहिरवार, इजरूल अली और नैतिक विश्वकर्मा की चौकड़ी ने जूनियर बालक टीम वर्ग के टीम डिस्टेंस इवेंट में कांस्य पदक जीता।

एशिया मिश्रित टीम चैम्पियनशिप से बाहर हुई पी.वी. सिंधु

नई दिल्ली, भारत की अनुभवी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु ने चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैम्पियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। सिंधु ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि हैमस्ट्रिंग में चोट से रिकवरी में उन्हें लंबा समय लगेगा इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। सिंधु वर्ष 2022 में एशिया मिश्रित टीम चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा वह ओलंपिक खेलों में दो बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं।

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल

एथलेटिक्स में दो नई स्पर्धाएं होंगी शामिल

ग्लास्गो, स्कॉटलैंड के ग्लास्गो शहर में अगले वर्ष आयोजित होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में दो नई स्पर्धाओं को शामिल किया गया है। ये दोनों स्पर्धाएं एथलेटिक्स से संबंधित है। इनमें 4 गुणा 400 मीटर मिश्रित टीम रिले और कॉमनवेल्थ मील इवेंट शामिल हैं।

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति ने मेडल इवेंट प्रोग्राम के दौरान कहा कि ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल-2026 में 200 से ज्यादा स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। समिति ने कहा कि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में दो नई स्पर्धाओं को शामिल किया गया है। इस बार 4 गुणा 400 मीटर मिश्रित टीम रिले और कॉमनवेल्थ मील स्पर्धाओं में भी एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश

commonwealth games
GLASGOW 2026

- **ग्लास्गो में 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे 23वें राष्ट्रमंडल खेल।**
- **इन खेलों में खिलाड़ी 200 से ज्यादा स्वर्ण पदकों के लिए लगाएंगे जोर।**
- **ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में 11 खेलों को किया गया है शामिल।**

करेंगे। कॉमनवेल्थ मील स्पर्धा को 1500 मीटर दौड़ की जगह राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। समिति ने कहा कि इस बार पैरा खेलों में भी ज्यादा पदक दांव पर होंगे।

तैराकी और ट्रैक साइक्लिंग की स्पर्धाओं के पदकों में वृद्धि

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति ने इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में तैराकी, ट्रैक साइक्लिंग और पैरा खेलों की स्पर्धाओं में इजाफा किया है। आयोजन समिति ने बताया कि इस बार तैराकी में 56 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जो कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में 4 ज्यादा हैं। इस बार तैराकी में पुरुषों की 800 मीटर और महिलाओं की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा पहली बार शामिल की गई है। इसी तरह ट्रैक साइक्लिंग और पैरा खेलों की पदक स्पर्धाओं में भी वृद्धि की गई है।

कॉमनवेल्थ मील स्पर्धा की 60 वर्ष बाद वापसी

राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ मील स्पर्धा की लगभग 60 वर्ष बाद वापसी हुई है। इससे पहले यह स्पर्धा अंतिम बार वर्ष 1966 में आयोजित जमैका राष्ट्रमंडल खेलों में आयोजित की गई थी, इसके बाद इस स्पर्धा को हटाकर 1500 मीटर दौड़ को शामिल किया गया था। आयोजकों ने बताया कि कॉमनवेल्थ मील स्पर्धा 1500 मीटर दौड़ के समान ही है, हालांकि इस स्पर्धा में एथलीट को 1609 मीटर की दूरी तय करनी होती है।

अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जेम्स ने रचा इतिहास

लॉस एंजेलिस, अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जेम्स अमेरिका की सबसे लोकप्रिय बास्केटबॉल लीग एनबीए के इतिहास में 40 अंक स्कोर करने वाले सबसे उम्रदराज बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। जेम्स ने लॉस एंजेलिस लेकर्स के लिए 42 अंक हासिल किए और अपनी टीम को गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के खिलाफ 120-112 से जीत दिलाई। जेम्स ने इस मामले में अपने हमवतन महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को पीछे छोड़ दिया है। जॉर्डन ने वर्ष 2003 में 40 वर्ष की आयु में 40 अंक लेकर यह रिकॉर्ड बनाया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

यूएनएचआरसी से अलग हुआ इजराइल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से अमेरिका के हटने की घोषणा के एक दिन बाद इजराइल भी इससे अलग हो गया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि इजरायल भी यूएनएचआरसी में भाग नहीं लेगा।

इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन ने अमेरिका के निर्णय का समर्थन करते हुए इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायली राष्ट्रपति ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में भाग न लेने के निर्णय का स्वागत करते हैं। इजराइल अमेरिका के साथ है और यूएनएचआरसी में भाग नहीं लेगा।

उन्होंने कहा कि यूएनएचआरसी ने यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आगे कहा कि यह परंपरागत रूप से मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं को जांच से बचने की अनुमति देकर उनकी रक्षा करता रहा है। इसके बजाय मिडिल ईस्ट में एकमात्र लोकतंत्र- इजराइल को जुन्नी रूप से शैतानी रूप में पेश करता रहा है। इस निकाय ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की बजाय एक लोकतांत्रिक देश पर हमला किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ स्पष्ट भेदभाव है।

बायरकतार टीबी3 ड्रोन का इंडोनेशिया में होगा निर्माण

तुर्किए के बायरकतार टीबी3 ड्रोन का निर्माण अब इंडोनेशिया में भी होगा। इस ड्रोन को दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक किलर ड्रोन माना जाता है। पिछले दिनों इंडोनेशिया और तुर्किए के बीच एक ऐतिहासिक डिफेंस समझौता हुआ। जिसके तहत इंडोनेशिया में इन अत्याधुनिक ड्रोन का उत्पादन किया जाएगा। समझौते के तहत इंडोनेशिया को 60 बायरकतार टीबी3 और 9 बायरकतार अकिंसी यूसीएवी हासिल होंगे। तुर्किए का बायरकतार टीबी3 ड्रोन, बायरकतार टीबी2 का अपडेटेड वेरिएंट है, जिसे पहले ही नागोर्नो-काराबाख, सीरिया और यूक्रेन युद्ध में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। यह ड्रोन छोटे रनवे वाले विमानवाहक पोतों से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा 2025 के दौरान छात्रों से बातचीत की

हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर दबाव के लिए खुद को तैयार करना चाहिए – प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में ''परीक्षा पे चर्चा'' (पीपीसी) के 8वें आयोजन के दौरान छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देशभर के छात्रों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कई विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पोषण विषय पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' घोषित किया और भारत के एक प्रस्ताव पर इसे दुनिया भर में प्रचारित किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने दृढ़ता से आग्रह किया है कि पोषण के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि उचित पोषण कई बीमारियों को रोकने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बाजरा को सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। यहां फसलें, फल जैसी अधिकांश चीजें विरासत से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों से मौसमी फल खाने का आग्रह किया और बच्चों को जंक फूड, तैलीय भोजन और मैदा से बने खाद्य पदार्थों से बचने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) के 8वें संस्करण में बच्चों के साथ बातें करते हुए

360 डिग्री विकास

शौक और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र रोबोट नहीं हैं और उनका समग्र विकास काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल अगली कक्षा में आगे बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि व्यापक व्यक्तिगत विकास के लिए है। प्रधानमंत्री ने इस पर प्रकाश डाला कि कैसे बागवानी जैसे विषय शुरुआती स्कूली शिक्षा के पाठ अप्रासंगिक लग सकते हैं, लेकिन वे समग्र विकास में योगदान करते हैं।

पोषण और स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए जोर दिया कि बीमार नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ है। शरीर की फिटनेस और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य पर नींद के महत्व पर कई शोध परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने मानव शरीर के लिए सूर्य के प्रकाश के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को प्रतिदिन कुछ मिनट सुबह की धूप में रहने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित किया।

दबाव पर काबू पाना

प्रधानमंत्री ने दबाव पर काबू पाने के विषय पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज ने इस विचार को गहराई से समाहित कर लिया है कि कक्षा 10वीं या 12वीं जैसी स्कूली परीक्षाओं में अधिक अंक नहीं लाना जीवन बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों पर दबाव और बढ़ जाता है। क्रिकेट मैच में गेंद पर बल्लेबाज की एकाग्रता का उदाहरण देते हुए उन्होंने बच्चों को बल्लेबाज की तरह बाहरी दबाव से बचने और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

खुद को चुनौती दें

प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से लोग खुद के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। उन्होंने आत्म-चिंतन के महत्व पर व्यक्तियों से बार-बार खुद से सवाल पूछने का आग्रह किया कि वे क्या बन सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं और कौन से कार्य उन्हें संतुष्टि प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी का ध्यान दैनिक बाहरी प्रभावों जैसे अखबारों या टीवी से नहीं होना चाहिए, बल्कि समय के साथ लगातार विकसित होना चाहिए।

भारत रक्षा नवाचार और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में वैश्विक अधिनायक बनने की ओर अग्रसर - रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 15वें एयरो इंडिया के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत परिवर्तन के एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है और देश रक्षा नवाचार तथा एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में वैश्विक अधिनायक बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में समग्र राष्ट्रीय सशक्तिकरण ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भरता के मंत्र का अंतर्निहित दर्शन था। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह दर्शन धीरे-धीरे हमारी राष्ट्रीय भावना में बदल चुका है और अब यह तेजी से राष्ट्रीय संकल्प एवं राष्ट्रीय क्रांति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक दशक पहले 65-70 प्रतिशत रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे, वहीं आज लगभग उतने ही प्रतिशत हथियार, प्लेटफार्म भारतीय धरती पर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसे मोड़ पर हैं, जहां पर लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली और नौसैनिक जहाज समेत कई रक्षा उत्पाद हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी भूमिका

रक्षा मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के अलावा, सशस्त्र सेनाएं देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिये ट्रंप और पुतिन के बीच बनी सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का वादा पूरा करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर अपनी सहमति दी है। ट्रंप ने कहा कि वह और पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सार्थक बातचीत की है। हमने यूक्रेन, मध्य पूर्व, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डॉलर की शक्ति और कई अन्य विषयों पर चर्चा की। हम दोनों ने अपने राष्ट्रों के महान इतिहास और इस तथ्य पर विचार किया कि हमने द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी।

ट्रंप ने लिखा कि हम दोनों ने अपने-अपने राष्ट्रों की ताकत और एक साथ काम करने से होने वाले लाभ के बारे में बात की। लेकिन सबसे पहले जैसा कि हम दोनों सहमत थे कि हम रूस-यूक्रेन युद्ध में होने वाली लाखों मौतों को रोकना चाहते हैं।

भारत में विश्वास आधारित आर्थिक शासन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस में 14वें भारत-फ्रांस सीईओ फोरम को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस फोरम ने रक्षा, एयरोस्पेस, उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइफ साइंसेज, कल्याण एवं जीवन शैली से जुड़ी कंपनियों के विविध समूह के सीईओ से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मिले प्रोत्साहन का उल्लेख किया।

उन्होंने स्थिर राजनीतिक व्यवस्था और पूर्वानुमानित नीतिगत इको-सिस्टम पर आधारित एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण पर चर्चा करते हुये हाल के बजट में घोषित सुधारों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र अब शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खुला है और एसएमआर एवं एएमआर प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी भागीदारी के लिए खुला है।

उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क दर संरचना को तर्कसंगत बनाया गया है और जीवनयापन में सुगमता को बढ़ाने के लिए सरलीकृत आयकर संहिता लाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधारों को जारी रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वास आधारित आर्थिक शासन स्थापित करने के उद्देश्य से नियामक सुधारों के लिए समिति का गठन किया गया है।

सक्रिय भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया

प्रधानमंत्री ने फ्रांसिसी कंपनियों को रक्षा, ऊर्जा, राजमार्ग, नागर विमानन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और सतत विकास के क्षेत्रों में भारत की विकास गाथा द्वारा पेश अपार अवसरों की ओर देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत के कौशल, प्रतिभा एवं नवाचार और इसके द्वारा शुरू किए गए एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और हाइड्रोजन से संबंधित नए मिशनों को वैश्विक स्तर पर मिली सराहना और उनमें दिखाई गई रुचि को रेखांकित किया।

संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट

बांग्लादेश हिंसा में हुई 1400 लोगों की मौत

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने बांग्लादेश में पिछले साल सरकार विरोधी छात्र प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। यूएन का दावा है कि वर्ष 2024 में हुई कार्रवाई में 1400 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें ज्यादातर लोगों की मौत के पीछे सुरक्षा बलों की गोलीबारी जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गोलीबारी तथा गिरफ्तारियां की और प्रताड़ित किया।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- डॉ. सुदाम खाड़े, मुद्रक- डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले।